राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 341 | रायपुर | शनिवार 13 दिसंबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज बस्तर जाएंगे

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

आईआईटी भिलाई में ऑर्बिटल केमसाइ सिम्पोजियम 2025 ने ग्लोबल साइंटिफिक एक्सीलेंस दिखाया

संवाददाता

दुर्ग आईआईटी भिलाई के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने 9 दिसंबर 2025 को ऑर्बिटल केमसाइ सिम्पोजियम 2025 को सफलतापूर्वक ऑर्गनाइज़ किया, जिसमें जाने-माने साइंटिस्ट, एल्युमनाई और स्टूडेंट्स एक दिन के साइंटिफिक एक्सचेंज के लिए एक साथ आए। कैंपस में हुए इस सिम्पोजियम में इनवाइटेड लेक्चर, एल्युमनाई इंटरेक्शन और केमिकल साइंसेज और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के फ्रंटियर एरिया में स्टूडेंट प्रेजेंटेशन का एक रिच सीक्वेंस था। इवेंट की शुरुआत केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट हेड डॉ. आर. मायल मुरुगन और सिम्पोजियम के कन्वीनर डॉ. अरूप मुखर्जी ने पार्टिसिपेंट्स का वेलकम किया और सालाना ऑर्बिटल केमसाइ सीरीज़ के पीछे के विज़न को आउटलाइन किया। इसके बाद प्ज् भिलाई के डायरेक्टर प्रो. राजीव प्रकाश ने इनॉगरल एड्रेस दिया, जिसमें उन्होंने एक मज़बूत रिसर्च इकोसिस्टम और इंटरनेशनल कोलेबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट के कमिटमेंट पर ज़ोर दिया।

टेक्निकल प्रोग्राम की शुरुआत प्रो. पीटर कॉम्बा (यूनिवर्सिटी ऑफ़हीडलबर्ग, जर्मनी) के एक खास

लेक्चर से हुई, जिन्होंने ÷क्यूरियोसिटी-ड्रिवन फंडामेंटल साइंस, इनोवेशन और ट्रांसफर, मेटल आयन-बेस्ड केमिस्ट्री के उदाहरण÷ पर बात की। सेशन में साइंटिफिक मोमेंटम को प्रो. होल्गर गोहल्के के एक असरदार लेक्चर के साथ जारी रखा गया, जिसमें उन्होंने एंजाइमोलॉजी और एग्रीकल्चरल साइंस में मॉलिक्यूलर मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन पर बात की। प्रो. प्रोसेनजीत डॉ, आईआईईएसआर बरहामपुर। लंच के बाद प्रो. सी. वी. शास्त्री (आईआईटी गुवाहाटी) ने छोटे मॉलिक्यूल एक्टिवेशन के लिए बाइफंक्शनल कैटलिस्ट और एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन में मेटल-ऑक्सीजन स्पीशीज पर अपनी इनवाइट टॉक से प्रोग्राम को और बेहतर बनाया। उनकी गहरी बातचीत ने एक इंटेलेक्चुअली दिलचस्प दिन के लिए माहौल तैयार किया। सुबह के सेशन में डॉ. दीप चौधरी ने एलुमनाई टॉक भी किया, जिसमें उन्होंने मैंगनीज-बेस्ड कैटेलिटिक ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन पर अपनी हालिया रिसर्च के साथ-साथ दूसरी स्टूडेंट टॉक भी पेश कीं। पूरे दिन ग्यारह स्टूडेंट प्रेजेंटेशन की एक सीरीज़ ने प्ज् भिलाई के स्कॉलर्स की अलग-अलग रिसर्च ताकत को दिखाया, जिसमें एडवांस्ड कैटेलिटिक सिस्टम, पॉलीमेरिक स्मार्ट मटीरियल, मेडिकल इमेजिंग के लिए मेटल कॉम्प्लेक्स, कम्प्यूटेशनल मैकेनिस्टिक स्टडीज़, विज़िबल-लाइट ट्रांसफॉर्मेशन और कार्बन-बेस्ड इलेक्ट्रोड और बिस्मथ पेरोव्स्काइट्स सहित एनर्जी मटीरियल शामिल थे। उनके योगदान ने मॉडर्न केमिकल साइंस और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च में इंस्टीट्यूट की बढ़ती मौजूदगी को दिखाया। इसके बाद प्रो. ई. ज्ञानमणि (आईआईटी रुड़की) ने माइक्रोड्रॉपलेट-असिस्टेड ऑर्गेनिक सिंथेसिस पर एक टॉक दी, जिसमें रिएक्शन मिनिएचराइज़ेशन में उभरते ट्रेंड्स पर रोशनी डाली गई। सिम्पोजियम में एक वाइब्रेंट पोस्टर सेशन और नेटवर्किंग इंटरैक्शन भी होस्ट किए गए, जिससे युवा रिसर्चर्स को कीमती एक्सपोज़र और मिलकर काम करने के मौके मिले। इवेंट का समापन ऑर्गनाइज़िंग कमिटी के क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ हुआ, जिसमें सभी अटेंडीज़ की एक्टिव पार्टिसिपेशन और इनसाइटफुल कंट्रीब्यूशन की तारीफ़ की गई। ऑर्बिटल केमसाइ सिम्पोजियम 2025 ने हाई-क्वालिटी रिसर्च और इंटरनेशनल साइंटिफिक एंगेजमेंट के लिए एक उभरते हुए सेंटर के तौर पर प्ज् भिलाई की भूमिका को फिर से कन्फर्म किया।

नगर निगम कर रहा मोबाइल टावरों का भौतिक सत्यापन

जगदलपुर,)। नगर पालिका निगम जगदलपुर द्वारा शहर में स्थापित सभी मोबाइल टावरों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में निगम ने इंडस टावर लिमिटेड, बीएसएनएल, जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड तथा एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर नेटवर्क शेयरिंग एंटीना से संबंधित समुचित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा के अनुसार जगदलपुर क्षेत्र में लगे सभी मोबाइल टावरों का स्थल पर जाकर सत्यापन किया जाना है, ताकि टावरों की वास्तविक स्थिति, उनमें लगे एंटीना एवं नेटवर्क शेयरिंग की सटीक जानकारी संकलित की जा सके। इसके लिए कंपनियों को 7 दिनों के भीतर अपने अधिकृत प्रतिनिधि भेजने तथा निगम की टीम के साथ मिलकर भौतिक सत्यापन संपन्न कराने को कहा गया है। जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सभी कंपनियाँ निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज एवं एंटीना संबंधी विवरण प्रस्तुत करें, जिससे आगामी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा सके। यह जानकारी महापौर संजय पांडे के दिशा निर्देश पर राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने दी ।

दिव्यांग बच्चों को मिला नया सहारा, चिरायु भैरमगढ़ की पहल से जीवन में लौटी मुस्कान

बीजापुर, आरएनएस)। विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी भैरमगढ़ डॉ. रमेश तिग्गा तथा बीपीएम भैरमगढ़ के मार्गदर्शन में चिरायु टीम भैरमगढ़ ने दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास की दिशा में सराहनीय कदम बढ़ाते हुए दो बच्चों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए। लाभार्थियों को प्रत्यारोपण हेतु रामनाथ भीमसेन भवन, समता कॉलोनी, रायपुर ले जाया गया, जहाँ विशेषज्ञ टीम द्वारा परीक्षण के बाद उन्हें आवश्यक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत

बीजापुर, जिला कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की प्रथम वर्षगांठ पर द्वितीय चरण के रूप में 100 दिवसीय जन-जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। बाल विवाह उन्मूलन को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से जिलेभर में व्यापक आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। अभियान का मुख्य लक्ष्य बच्चों, बालिकाओं, महिलाओं एवं समुदाय को बाल विवाह के दुष्परिणाम, उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। वर्ष 2025-26 में जिले की 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त बनाना लक्षित है।

मुख्यमंत्री के विडियों में छेड़छाड़ करने वालो के खिलाफ भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने एफआईआर दर्ज कराई

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संबोधन के वीडियो में छेड़छाड़ एवं एडिट कर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास करने वालों के खिलाफएफआई.आर. दर्ज कराने भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज एसपी कार्यालय पहुँचाकर अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग की। इस दौरान शहर जिला रमेश ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी, शताब्दी पांडेय, डॉ. किरण बघेल, विधि प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक बृजेश पांडेय, जिला महामंत्री अमित मैशरी, गुंजन प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष सत्यम दुवा, अकबर अली, नवीन शर्मा, जिला प्रवक्ता शिवजलम दुबे, पुष्पेन्द्र उपाध्याय, अर्पित सूर्यवंशी, वासु शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे।

रेलवे का आदेश : नियमित, संविदा कर्मचारियों के क्यूआर कोड लगे अलग-अलग रंग के होंगे परिचय पत्र

जबलपुर. संवाददाता

अब देशभर के रेलवे कर्मचारियों और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को एक नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा. रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने सभी जोन को इसके लागू करने का आदेश दे दिया है. नया पहचान पत्र क्यूआर कोड आधारित होगा, जिससे कर्मचारियों की जानकारी डिजिटल तरीके से आसानी से उपलब्ध होगी. इस रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में एक पत्र पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय सहित देश के सभी रेल जोनों को भेज दिया है.

नियमित कर्मियों का होगा पीले रंग का कार्ड नियमित रेलकर्मियों का पहचान पत्र पीले रंग का होगा, जबकि संविदा कर्मचारियों के लिए नारंगी रंग का कार्ड जारी किया जाएगा. यह पहचान पत्र न केवल कर्मचारी की पहचान साबित करेगा, बल्कि संविदा कर्मचारियों के लिए कार्यालय में प्रवेश का प्रमाण भी होगा. पहचान पत्र पर कर्मचारी की तस्वीर, हस्ताक्षर, नाम, पद, विभाग, जारी होने और वैधता की तिथि तथा जारीकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर शामिल होगा. क्त्र कोड स्कैन करने पर कर्मचारी का नाम, पता, पद, कार्यस्थल, आधार नंबर, कार्ड जारी होने और वैधता की तिथि तथा कार्ड जारी करने वाले अधिकारी की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी. संविदा कर्मचारियों के कार्ड में स्पष्ट रूप से-ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अंकित रहेगा.

कर्मचारियों की पहचान, सुरक्षा सुनिश्चित रेल मंत्रालय के अनुसार, यह कदम कर्मचारियों की पहचान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रवेश प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. कर्मचारी अब अपने डिजिटल पहचान पत्र के माध्यम से कार्यालय में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे और उनके रिकॉर्ड का प्रबंधन भी आसान होगा. इस नई पहल से रेलवे में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों की सुविधा में भी सुधार होगा, जिससे सभी जोन में कार्यरत कर्मचारियों को समान रूप से लाभ मिलेगा.

मनरेगा से बदला बांगोली का जीवन, अब गांव में ही मिलेगा राशन

बीजापुर,

भैरमगढ़ विकासखंड के इंद्रावती नदी पार स्थित नियद नेल्लानार ग्राम पंचायत बांगोली गांव के ग्रामीणों को अब राशन के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। वर्षों से माओवाद प्रभावित इस क्षेत्र के बांगोली, सतवा और मरकापाल के निवासियों को प्रतिमाह 18 किलोमीटर दूर भैरमगढ़ जाकर उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करना पड़ता था। बरसात के दिनों में इंद्रावती नदी पार करना अत्यंत जोखिमपूर्ण हो जाता था, जिससे 524 राशनकार्डधारी परिवारों को नियमित खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

जिला प्रशासन की पहल तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना और जिला खनिज न्यास निधि (DMF) के संयुक्त सहयोग से ग्रामीणों की यह बड़ी समस्या अब समाप्त होने जा रही है। लगभग 11 लाख 76 हजार रुपये की लागत से बांगोली में खाद्यान भंडारण सह उचित मूल्य दुकान भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। नए भवन के तैयार होने के साथ ही गांव में ही राशन वितरण की व्यवस्था जल्द शुरू होने वाली है। स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों में इस सुविधा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। मरकापाल की सरपंच बसंती नेताम ने बताया कि ग्रामीणों को पहले राशन के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन अब 524 परिवारों को गांव में ही सुगमता से खाद्यान्न मिलेगा, जिससे उनकी बड़ी समस्या दूर हो गई है। इसी तरह सतवा के उपसरपंच जुनकी कोरसा और बांगोली के मानसू भास्कर ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को राशन लाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। पहले यह कार्य किसी चुनौती से कम नहीं था।

उचित मूल्य दुकान के इस नए भवन से इन तीनों गांवों में राहत, सुरक्षा और सुविधा की नई उम्मीद जागी है।

द्वितीय सोपान स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर बम्हनी चारभाठा में संपन्न

राजनांदगांव /छुरिया,

8 दिसंबर 2025 भारत स्काउट एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार 5 से 8 दिसंबर 2025 तक श्री विश्रामदास बैरागी शासकीय हाई स्कूल बम्हनी चारभाठा में द्वितीय सोपान प्रशिक्षण एवं जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का संचालन राज्य मुख्य आयुक्त माननीय इंदरजीत सिंह खालसा, राज्य सचिव जीतेन्द्र साहू, राज्य उपाध्यक्ष राजेन्द्र गोलछा, जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला आयुक्त स्काउट प्रवास कुमार सिंह बघेल के मार्गदर्शन में किया गया।

साथ ही जिला अध्यक्ष उमेश हत्थेल, जिला मुख्य आयुक्त महेश खंडेलवाल, जिला संगठन आयुक्त मयूख श्रीवास्तव एवं जिला सचिव देवेन्द्र अंबादे का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। शिविर में विकासखंड छुरिया के 27 हाई एवं हायर सेकंडरी विद्यालयों के 103 स्काउट, गाइड, रोवर एवं रेंजर प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को स्काउट परिचय, नियम-प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा गीत, बी.पी. सिक्स, रोप नॉटिंग, फर्स्ट एड, मैपिंग सहित

स्काउटिंग से जुड़े सभी आवश्यक विषयों का अभ्यास व परीक्षण कराया गया। इसके अतिरिक्त कैम्प सांग, विभिन्न खेल, समूह गतिविधियाँ एवं कैम्प फायर कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागियों को अनुशासन, नेतृत्व, सेवा भावना और टीमवर्क का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर को सफल बनाने में विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रशांत चितवर्कर का मार्गदर्शन एवं नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल तथा प्राचार्य हेमलता भंवर का विशेष सहयोग रहा। संचालन मंडल में रामनारायण साहू (विकासखंड सचिव), नीलकंठ धुर्वे (पूर्व सचिव), दाताराम निषाद (शिविर संचालक), तुलसीराम साहू (क्वार्टर मास्टर), रोवर लीडर डेहर साहू, धर्मेन्द्र कुमार रजक, गिरधारी साहू, योगेन्द्र कुमार, भूपेन्द्र कैवर्त की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गाइड टीम में कीर्ति साहू, रक्षा शाह, आशा ताम्रकार, तथा फूलेता कोर्राम का सराहनीय योगदान रहा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत बम्हनी चारभाठा की सरपंच मीना ध्रुवे, शाला विकास समिति अध्यक्ष तोरण दास वैष्णव, पंच सारिका चौरे एवं समस्त ग्रामवासियों का सहयोग उल्लेखनीय रहा।

दुगाटोला के दो युवाओं का राज्य पुलिस सेवा में चयन

गांव के माटीपुत्रों की सफलता से अंचल में खुशी की लहर

राजनांदगांव।

वनांचल क्षेत्र मोहला-मानपुर के ग्राम दुगाटोला (सोमाटोला) ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि मजबूत हौसले और दृढ़ संकल्प के सामने संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती। गांव के दो होनहार युवा जयंत यादव/जलिंधर यादव एवं मुन्ना लाल/देवनंद राम का छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा में चयन होने से गांव, परिवार और समूचे अंचल में हर्ष का माहौल है।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसे दुगाटोला की पगडंडियों पर कभी नंगे पांव दौड़ने वाले ये युवा आज राज्य सेवा में चयनित होकर गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि से भरपूर यह गांव हमेशा से संघर्ष,

मेहनत और कड़ी साधना की भूमि रहा है। कठिन परिस्थितियों में भी यहां के युवा कभी पीछे नहीं हटते-इसी का परिणाम है यह उल्लेखनीय उपलब्धि।

इन माटीपुत्रों की उपलब्धि यह साबित करती है कि दुगाटोला के युवाओं में न केवल मेहनत की ताकत है बल्कि देश सेवा और जन सेवा का जज़्बा भी भरा है। इस सफलता ने क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी नई दिशा और प्रेरणा प्रदान की है।

उनकी इस उपलब्धि पर गांव एवं पूरे इलाके में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बधाई देने वालों में-

दीपचंद कोरटिया, बी.एल. देशमुख, के.एल. माहले, हेमलाल चुरेंद्र, किशन देशमुख, पूनाराम लेड़िया, लक्ष्मण माहले, हुमन कोरटिया, कमलेश्वर भुवार्य, भुवन बढ़ाई, यशवंत माहले, खेदूराम लेड़िया, हिरा सिंह माहले, लाला भुवार्य, श्रीमती पदमा चुरंद्र, सोहद्रा कोरटिया, अंबिका भुवार्य, रेणुका माहले, सुश्री प्रेरणा लरिया, राजु कोरटिया, ईवा भुवार्य, निर्मल कोरटिया सहित कर्मचारी प्रकोष्ठ के सदस्य शामिल हैं।

इसके साथ ही सरपंच पुष्पेंद्र भुवार्य, ग्राम पटेल तिलक भुवार्य, ललित यादव, बरातू सोनी, लिखन सिन्हा, हिंसा चौरे, तोरण देशमुख एवं बड़ी संख्या में युवाओं ने दोनों चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं।

सभी ने जयंत यादव एवं मुन्ना भैसारे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

गायत्री मंत्र मानव जीवन को ऊर्जावान और संस्कारित बनाते हैं : मुख्यमंत्री विष्णु देव

0 मुख्यमंत्री हसौद में 251 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ में हुए शामिल

0 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 140 नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद

रायपुर, । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सक्ती जिले के ग्राम हसौद में आयोजित भव्य 251 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को आध्यात्मिक एकता, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम बताया। उन्होंने कहा कि मां महामाया की पावन भूमि हसौद में 251 कुंडों में एक साथ सम्पन्न हो रहा यह महायज्ञ छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक परंपरा को नई ऊंचाई देता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा-500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हुआ। छत्तीसगढ़ तो स्वयं भगवान श्रीराम का ननिहाल है-माता कौशल्या की पावन भूमि है। उन्होंने कहा कि

प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्गों की उन्नति और कल्याण के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। रामलला दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से अब तक 38 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला का दर्शन किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 सिद्धियों और शक्तियों के प्रतीक हैं, जो मानव जीवन को ऊर्जा, सदाचार और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांतिकुंज हरिद्वार के कुलपति डॉ. चिन्मय पण्डया ने मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट किया। इस अवसर पर कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही देशभर से आए अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। 140 नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद - कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हसौद में परिणय-सूत्र में बंधने वाले 140 नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएँ और आशीर्वाद दिया। जैतखाम में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हसौद प्रवास के दौरान जैतखाम पहुँचकर विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति, कल्याण एवं निरंतर प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के सत्य, अहिंसा, समानता, सामाजिक समरसता तथा 'मनखे-मनखे एक समान' के संदेश हमें समाज में सद्भाव और एकता का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने जनसमूह से आह्वान किया कि इन आदर्शों को आत्मसात कर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय योगदान दें।

छत्तीसगढ़ में हादसा : भिलाई स्टील प्लांट के पीबीएस-2 के गैस लाइन में लगी आग

भिलाई. छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन नंबर दो (पीबीएस-2) के गैस पाइपलाइन में शुक्रवार की दोपहर 12:15 के करीब आग लग गई. इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. जिस पाइपलाइन में आग लगी है उसे भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक-8 महामाया को गैस की आपूर्ति होती है.

इस पाइप लाइन से आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है परंतु आग बुझ नहीं पाई है. आग को बुझाने के लिए अन्य तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है. किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस आठ में धीरे-धीरे उत्पादन को कम किया जा रहा है, जिससे नुकसान कम हो. आग पर काबू पाने के लिए बीएसपी फायर ब्रिगेड का अमला लगा हुआ है. गैस पाइपलाइन जिस स्ट्रक्चर पर लगा हुआ है वह स्ट्रक्चर ना गिरे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. फिलहाल आसपास के पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है. किसी भी कर्मचारी को आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. बीएसपी के अधिकारी सहित सेफ्टी टीम व फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है.

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का दूसरा चरण शुरू, 180 नए गांव जुड़े बस सुविधा से

ग्रामीण परिवहन को नई रफ्तारः मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ

0 बस्तर और सरगुजा में परिवहन क्रांति, ग्रामीण बस योजना का विस्तार

रायपुर, । छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के सुदूर वनांचलों में ग्रामीण परिवहन को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने आज एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से योजना के द्वितीय चरण का औपचारिक शुभारंभ किया तथा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों के 23 मार्गों पर 24 नई बसों का संचालन प्रारंभ हुआ है, जिससे 180 गांव सीधे बस सुविधा से जुड़ गए हैं। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में शामिल अनेक ग्रामीण उसी बस में सवार होकर पहुंचे, जिसे योजना के प्रथम चरण में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से आत्मीय चर्चा करते हुए बताया कि अब दूरस्थ इलाकों से ब्लॉक मुख्यालयों तक पहुंचना पहले की तुलना में काफी सहज और सुगम हो गया है। सुकमा-दोरनापाल-कोंटा मार्ग से पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि वे लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा बस से कर कार्यक्रम तक पहुंचे, जबकि पूर्व में यह यात्रा बेहद कठिन और समयसाध्य थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से अलग न रहे। यह योजना न केवल परिवहन सुविधा बढ़ा रही है, बल्कि ग्रामीणों को शहरों और सेवा संस्थानों से जोड़ते हुए सामाजिक एवं आर्थिक समानता को भी मजबूती प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में यह योजना एक मील का पत्थर सिद्ध हो रही है, जिससे लोगों को सुरक्षित, समयबद्ध और सुविधाजनक यात्रा का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने योजना से लाभान्वित होने वाले 180 गांवों के सभी ग्रामीणों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेहतर यातायात सुविधाएँ अब उनके जीवन को पहले से अधिक सुगम बनाएंगी और तरक्की के नए मार्ग खोलेंगी। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जिन दुर्गम और वनांचल क्षेत्रों तक कभी यातायात की सुविधा नहीं पहुंची थी, वहाँ भी अब बस सेवाएँ प्रारंभ हो रही हैं।

यह योजना विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा के जनजातीय बहुल इलाकों के लिए एक वरदान के रूप में उभर रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के प्रथम चरण की शुरुआत 04 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत 250 गांवों को बस सेवाओं से जोड़ा गया था। अब द्वितीय चरण की शुरुआत के साथ इस संख्या में और वृद्धि हुई है तथा 180 गांव और जुड़ गए हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, कर्मचारियों का जन्मदिन बना यादगार प्रोजेक्ट आओ बाँटें खुशियाँ के तहत सुपरवाइजर प्रभाती कर्मकार ने बच्चों संग साझा की खुशियाँ

रायपुर, 11 दिसम्बर (आरएनएस)। जिले में शासकीय कर्मचारियों के जन्मदिन अब केवल व्यक्तिगत आयोजन नहीं रह गए हैं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित प्रोजेक्ट आओ बाँटें खुशियाँ का उद्देश्य ही है - खुशियों को बाँटना, और इस पहल को शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ अपना रहे हैं। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने प्रभाती कर्मकार को जन्मदिन की बधाई दी एवं प्रोजेक्ट आओं बांटें खुशियां के तहत डिजिटल प्रमाण पत्र भेजा। इसी क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर प्रभाती कर्मकार ने आरंग ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र 1 भानसोज में जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के साथ केक काटकर, फल और पौष्टिक आहार वितरित कर इस दिन को विशेष बनाया।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि

रायपुर, (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पुण्यतिथि (12 दिसंबर) पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गुप्त जी ने खड़ी बोली को न केवल काव्य की गरिमा प्रदान की, बल्कि उसे राष्ट्रीय चेतना का सशक्त वाहक बनाया। स्वतंत्रता संग्राम के चुनौतीपूर्ण समय में मैथिलीशरण गुप्त जी की रचनाओं ने देशभक्ति, स्वाभिमान और सामाजिक जागरण की ऐसी लौ प्रज्वलित की, जिसने जन-मानस को एकजुट किया। उनकी कालजयी कृति भारत-भारती सहित अनेक काव्य-रचनाएँ आज भी राष्ट्रभावना और सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन में अमूल्य योगदान देती हैं। इन्हीं अद्वितीय सेवाओं के कारण उन्हें सम्मानपूर्वक 'राष्ट्रकवि' की उपाधि से विभूषित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गुप्त जी का साहित्य भारतीय समाज के मूल्यों, संवेदनाओं और राष्ट्रीय आदर्शों का जीवंत दस्तावेज है। उनकी रचनाएँ आने वाली पीढ़ियों को सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी।

रेल यात्रा का नया डिजिटल साथी – रेलवन ऐप

0 रेलवे सेवाओं का एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

0 सुपर ऐप 'रेलवन' ने रेलवे यात्री सुविधाओं को बनाया और अधिक सरल व आसान

रायपुर, संवाददाता

भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए विभिन्न सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत मोबाइल सुपर ऐप 'रेलवन (स्वरेल)' का बीटा संस्करण शुरू किया गया । यह ऐप रेलवे टिकट बुकिंग (आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफ़ॉर्म टिकट), ट्रेन पूछताछ, ई-कैटरिंग, शिकायत निवारण एवं अन्य यात्री सेवाओं से जोड़ते हुए रेलवे यात्रा को और अधिक सुगम, आधुनिक एवं सुविधाजनक बना रहा है । यह पहल रेलवे उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपरऐप भारतीय रेलवे सेवाओं तक अधिक तीव्र, सरल और अधिक कुशल पहुँच प्रदान करता है ।

ऐप का प्रयोग : इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें ।

रेलकनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता अपने पहचान के प्रमाण के साथ सीधे लॉग इन कर सकते हैं ।ऐप के माध्यम से उपलब्ध प्रमुख सेवाएँ

आरक्षित, अनआरक्षित, प्लेटफार्म टिकट की सुविधा टिकट बुकिंग और रद्दीकरण

ट्रेन की रियल-टाइम पूछताछ एवं लाइव स्टेटस ई-कैटरिंग सेवा द्वारा भोजन की ऑनलाइन बुकिंग शिकायत एवं सुझाव दर्ज कराना तथा उनकी स्थिति देखना पार्सल बुकिंग एवं संबंधित जानकारी यात्रियों को मिलने वाली लाभ एक ही ऐप से अनेक सेवाओं का लाभ

समय, ऊर्जा एवं कागज़ी प्रक्रिया की बचत

पारदर्शी, आधुनिक और उत्तरदायी सेवा प्रणाली शिकायतों का त्वरित निवारण रेलवन ऐप यात्रियों के लिए तकनीकी रूप से उन्नत और समय की बचत करने वाला प्लेटफार्म है। इस ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की स्थिति तक सभी जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध हो जाती है, जिससे रेलवे सेवाएँ और अधिक तेज एवं भरोसेमंद बन गई हैं।

जहाँ शहीद हुए थे वीर नारायण सिंह, वहाँ मनाया गया उनका 168 वाँ शहादत दिवस

बच्चों ने किया नाटक मंचन, वरिष्ठ कलाकारों का गायन, कवियों का काव्य पाठ, पुस्तक विमोचन और इतिहासकारों का सम्बोधन भी हुआ

रायपुर, । वैसे तो अमर शहीद वीर नारायणसिंह के 168 वें शहादत दिवस के मौके पर कल 10 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम हुए, लेकिन एक महत्वपूर्ण आयोजन उनके शहादत स्थल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक जय स्तंभ चौक पर भी हुआ, जहाँ देश की आज़ादी के युद्ध में 1857 में 10 दिसम्बर को ही वह शहीद हो गए थे ।

उनकी पुण्य स्मृति में शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी और छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया । आयोजन में गीत -संगीत,स्कूली बच्चों के नाटक मंचन, वरिष्ठ कवियों के छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ और प्रबुद्धजनों के सम्बोधनों में वीर नारायण सिंह के महान संघर्षों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई ।

उल्लेखनीय वीर नारायणसिंह सोनाखान के प्रजा हितैषी ज़मींदार थे और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी राज के खिलाफ़ हुए युद्ध में छत्तीसगढ़ के अग्रणी महान योद्धा बनकर उभरे थे । इतिहासकारों के अनुसार राजधानी रायपुर का जय स्तंभ चौक वही जगह है, जहाँ 10 दिसम्बर 1857 के दिन वीर नारायण सिंह को राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी की हुकूमत ने फाँसी की सजा दी थी । इसी जगह पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अमर शहीद की घुड़सवार प्रतिमा के साथ एक अच्छा स्मारक भी बनवाया गया है ।

वीर नारायणसिंह के 168 वें शहादत दिवस के उपलक्ष्य में कल यहाँ आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और अखंड शहीद जवान ज्योति प्रज्वलित की गई ।सर्वप्रथम वरिष्ठ पंडवानी कलाकार श्री चेतन देवांगन और उनके साथियों ने शहीद वीर नारायण सिंह की शौर्य गाथा को पंडवानी तर्ज पर आकर्षक ढंग से पेश किया । सुप्रसिद्ध कलाकार ममता आहार के निर्देशन और गायन तथा संतोष चंद्राकर के संगीत के साथ रायपुर के नन्हें स्कूली बच्चों ने अमर शहीद पर केंद्रित नाटक का मंचन किया, जिसे खूब प्रशंसा मिली । कार्यक्रम में वीर नारायणसिंह की जीवनी पर आधारित ममता अहार की एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ लोक कलाकार श्री राकेश तिवारी ने वीर नारायण सिंह की संघर्ष -गाथा को आल्हा तर्ज पर प्रस्तुत किया । उन्हें भी खूब तारीफ़मिली ।

प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत जे.आर. दानी स्कूल में बच्चों की हुई निःशुल्क हृदय जांच, 90 बच्चों की हुई स्क्रीनिंग

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज जे.आर.दानी हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर में 90 बच्चों की स्क्रीनिंग किया गया। प्रोजेक्ट धड़कन के तहत अब तक जिले के 12 हजार 638 बच्चों का स्क्रीनिंग किया जा चुका है जिसमें 6088 लड़के एवं 6550 लड़कियां शामिल हैं जिसमें 12 बच्चे सस्पेक्टेड मिले हैं।

बिलासपुर–नागपुर–बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस : सफलता के तीन गौरवपूर्ण वर्ष

रायपुर, संवाददाता।

भारतीय रेलवे की आधुनिकतम और श्रेष्ठतम वंदे भारत एक्सप्रेस, जो बिलासपुर और नागपुर के मध्य संचालित होती है, ने अपने तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रतिष्ठित ट्रेन को तीन वर्ष पूर्व आज ही के दिन हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था। यह गाड़ी अपनी उच्च गति, आधुनिक सुविधाओं और समयबद्ध संचालन के लिए प्रसिद्ध है। 3 वर्षों के इस गौरवशाली अवसर पर कोचिंग डिपो बिलासपुर ने पूरे उत्साह के सभी कोचों को तिरंगे गुब्बारों से सुंदर रूप से सजाया गया, जिससे सम्पूर्ण परिसर में राष्ट्रीय गौरव और उल्लास का वातावरण निर्मित हुआ। यह सजावट यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी और इस उपलब्धि का प्रतीकात्मक सम्मान भी। बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत ने इस साल मार्च मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की पहली आईएसओ 9001:2015

सर्टिफाइड ट्रेन बनने का खिताब भी अपने नाम करवाया है । जो उच्चतम गुणवत्ता मानकों, उत्कृष्ट प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री संतुष्टि का प्रमाण है । यह उपलब्धि न केवल इस ट्रेन की विश्वसनीयता को बढ़ाती है, बल्कि भारतीय रेलवे की नवाचार और सेवा सुधार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। इस वंदे भारत रेक का रखरखाव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कोचिंग डिपो, बिलासपुर में किया जा रहा है । कोचिंग डिपो बिलासपुर के अधिकारियों , सुपरवाइजर और कर्मचारियों ने नई तकनीक से युक्त इस वंदे भारत रेक के संचालन में अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव का प्रदर्शन करते हुए इसे पूरी दक्षता के साथ संचालित किया है । पिछले तीन वर्षों में इस ट्रेन ने बिना किसी तकनीकी समस्या के सुचारु और निर्बाध रूप से अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं । पिछले वर्ष इस वंदे भारत रेक का प्रथम शॉप शेड्यूल-1 कोचिंग डिपो बिलासपुर में सफलतापूर्वक पूरा किया गया । इस उपलब्धि के साथ कोचिंग डिपो बिलासपुर भारतीय रेल का पहला कोचिंग डिपो बन गया, जिसने यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रियों के सफर को न केवल आरामदायक और सुरक्षित बनाया है, बल्कि यात्रा समय को भी उल्लेखनीय रूप से कम किया है । यह गाड़ी लगभग 412 किलोमीटर की दूरी को केवल 5.5 घंटे में तय करती है । इसमें उत्कृष्ट बैठक व्यवस्था, वाई-फाई, इन्फोटेनमेंट प्रणाली और ऑटोमैटिक दरवाजों जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह ट्रेन न केवल व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि क्षेत्रीय समृद्धि में भी योगदान दे रही है ।

नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होगा साहित्य उत्सव

रायपुर, (आरएनएस)। अगले वर्ष 23 दिसंबर से नवा रायपुर में होने वाले रायपुर साहित्य उत्सव के लिए राज्य शासन ने सलाहकार समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में नौ सदस्य बनाए गए हैं। समिति में सदस्य के रूप में अनंत विजय, डॉ. सुशील त्रिवेदी, सतीश कुमार पंडा, जयमति कश्यप, संजीव कुमार सिन्हा, शंशाक शर्मा, पंकज कुमार झा और विवेक आचार्य को भी शामिल किया गया है। समिति रायपुर साहित्य उत्सव के सफल और प्रभावी आयोजन के लिए विशेष सलाह देगी। इसके साथ ही साहित्यकारों के चयन और आयोजन के विषयों पर भी आयोजकों को सहयोग करेगी। जनसंपर्क संचालनालय के आयुक्त डॉ. रवि मित्तल समिति के सदस्य सचिव होंगे। उल्लेखनीय है कि नए वर्ष की शुरुआत के साथ आगामी महीने रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होगा, जिसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे। राज्य स्थापना के रजत वर्ष पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा इस आयोजन की परिकल्पना की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संकल्पना पर आधारित इस आयोजन की व्यापक कार्ययोजना मात्र दो माह में तैयार की गई है। यह तीन दिवसीय महोत्सव 23, 24 एवं 25 जनवरी 2026 को जनजातीय संग्रहालय के समीप आयोजित होगा। इस उत्सव में कुल 11 सत्र शामिल होंगे।

शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान, आत्मगौरव, संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक - मुख्यमंत्री

नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, सियान सदन और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना अंतर्गत बस सेवा प्रारंभ करने की घोषणा

o 101 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

o मुख्यमंत्री सोनाखान में आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान छत्तीसगढ़ के आत्मगौरव, संघर्ष और स्वाभिमान का अमर प्रतीक है। वे आज सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करने पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के वंशजों को सम्मानित किया और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री ने सोनाखान में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना अंतर्गत बस सेवा प्रारंभ करने, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 75 लाख रुपये, सियान सदन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तथा मड़ई मेला स्थल में शौचालय निर्माण के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोनाखान में इको-टूरिज्म विकास और सड़क निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान आगामी बजट में शामिल किए जाएंगे जिससे इस ऐतिहासिक स्थल को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार एवं सुविधाओं में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजी शासन के अत्याचार के विरुद्ध गरीबों, किसानों और वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हुए एक ऐसे वीर सपूत थे, जिन्होंने भीषण अकाल के समय गरीबों में अनाज बांटकर मानवता की ऐतिहासिक मिसाल पेश की। अंग्रेजी हुकूमत ने 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी, किंतु उनका बलिदान सदियों से संघर्ष, स्वाभिमान और अन्याय के प्रतिकार की प्रेरणा देता आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'गारंटी' के तहत अधिकांश वादों को पूरा किया है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर काम कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने रायपुर के जयस्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को फांसी दी थी। वे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हुए और उनका बलिदान पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि विकास और कल्याण के लिए सरकार सतत् कार्यरत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 101.44 करोड़ रुपये की लागत के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के 10 हितग्राहियों को घरों की चाबियाँ सौंपी तथा 'हम होंगे कामयाब' कार्यक्रम के अंतर्गत 37 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आदिवासी समाज के पाँच प्रतिभावान छात्रों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। समारोह में वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े तथा शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज राजेंद्र दीवान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सभी जिलों में होगीं कविता-कहानी प्रतियोगिताएं

पुरस्कार भी मिलेंगे, जिले के विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जायेगा

o विद्यार्थियों से 30 दिसंबर तक ली जायेगी स्वरचित कहानियां और कविताएं

रायपुर,। नवा रायपुर में अगले महीने होने वाले साहित्य उत्सव के पहले प्रदेश के सभी जिलों में महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए कहानी एवं कविता प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इन दोनों प्रतियोगिताओं में जिला स्तर पर विजेताओं को पुरस्कार भी मिलेंगे। जिले के विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल किया जायेगा और सर्वोत्कृष्ट कहानी तथा कविता को रायपुर साहित्य उत्सव में पुरस्कृत किया जायेगा। इस प्रतियोगिता के लिये जिलेवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के इच्छुक छात्र-छात्राएं अपनी स्वरचित कविता और कहानी 30 दिसंबर 2025 तक जिले के नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। 30 दिसंबर के बाद मिली कहानियों-कविताओं को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जायेगा। प्रदेश की समृद्धशाली साहित्यिक विरासत को लोगों तक पहुंचानें और साहित्य लेखन में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए नवा रायपुर में 23-25 जनवरी 2026 तक रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन होगा। साहित्य उत्सव के तहत जिलेवार महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाली कविता-कहानी प्रतियोगिताओं में पहले पुरस्कार के रूप में 5,100 रूपए, दूसरे पुरस्कार के रूप में 3,100 रूपए और तीसरे पुरस्कार के रूप में 1,500 रूपए की धनराशि दी जाएगी।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

एसआईआर पर विपक्ष ना फैलाये भ्रम

एसआईआर पर विपक्ष भ्रम ना फैलाये। किसी प्रक्रिया के जारी रहने के दौरान उसके नियम बदलते रहें, तो उसे इसकी मिसाल ही समझा जाएगा कि संबंधित संस्था ने काम शुरू करने के पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर यह बात पूरी तरह लागू होती है। विपक्ष को फिलहाल अपने लोकहित के लिये किये गये कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि जनता लोकतंत्र में मतदान विकास देखकर करती है ना कि आरोप प्रत्यारोप देखकर । अमित शाह ने ठीक ही कहा कि भ्रम और गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है विपक्ष द्वारा ।

सोशल मीडिया का बढ़ता वर्चस्व और खोता हुआ बचपन

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

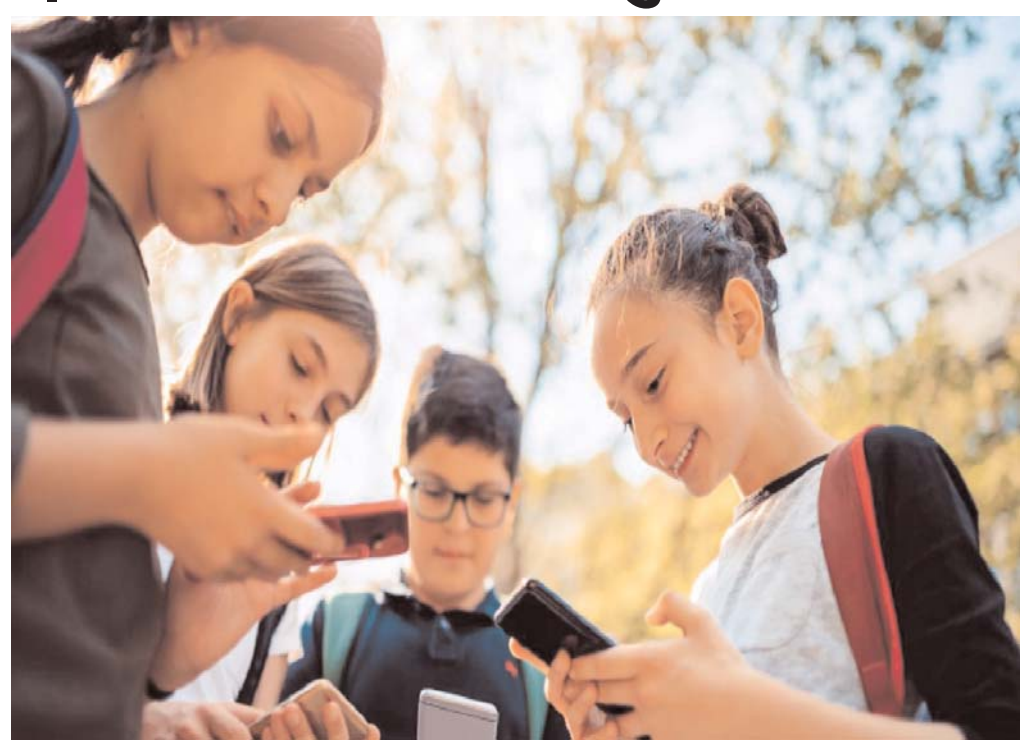

पिछले एक दशक में जिस सोशल मीडिया को आधुनिकता की उपलब्धि, अभिव्यक्ति की आजादी और वैश्विक संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम माना गया था, उसी सोशल मीडिया ने अब अपने छिपे डरावने एवं वीभत्स चेहरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी देश, जो कल तक इसके गुणगान करते नहीं थकते थे, अब उसके दुष्परिणामों से भयभीत होने लगे हैं। यह भय यूं ही नहीं है-अनेक देशों में बच्चों की आत्महत्याओं, हिंसक व्यवहार, मानसिक विकारों, नशे जैसे डिजिटल व्यसनों और सामाजिक विकृतियों के बढ़ते आंकड़ों ने सोशल मीडिया की वास्तविकता का पर्दाफाश किया है। इसी पृष्ठभूमि में आस्ट्रेलिया की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाकर विश्व-समुदाय को चेताया भी है और झकझोर भी दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से वह अधिकार वापस ले लिए हैं, जिनके दुरुपयोग ने बच्चों के जीवन और अभिभावकों की मानसिक शांति को संकट में डाल दिया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सुधार बच्चों को 'बचपन जीने का अधिकार' लौटाने के लिए है-उन जिंदगियों को नया मोड़ देने के लिए है जो सोशल मीडिया ने समय से पहले वयस्कता, अस्वस्थता, तनाव और विकृतियों में धकेल दी थीं। इतना ही नहीं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट नहीं हटाने पर लगभग पाँच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान देश का रुख साफ करता है कि अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस पहल के बाद पश्चिमी जगत में सुगबुगाहट बढ़ी है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक सवाल उठ रहे हैं कि यदि ऑस्ट्रेलिया यह साहस दिखा सकता है तो वे क्यों नहीं? यह सुगबुगाहट केवल सरकारों में ही नहीं है-उन अभिभावकों में भी है जिन्होंने सोशल मीडिया को अपने बच्चों की आत्महत्या, अवसाद और चरित्र-भंग का मूल कारण मानना शुरू कर दिया है। वास्तव में, इस संकट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों ने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ऐसे एल्गोरिद्म बनाए, जो उनका अधिकतम समय खाएं, उनकी जिज्ञासाओं को उकसाएं और उनके भीतर छिपी संवेदनशीलता का दोहन करके उन्हें सोशल मीडिया निर्भरता की स्थिति तक ले जाएं। इन प्लेटफॉर्मों पर वयस्क सामग्री, द्विअर्थी वीडियोज, हिंसक गेम्स, 'लाइक-फॉलोअर' जैसे डिजिटल भ्रमों का ऐसा सैलाब है जिसने बच्चों की मनोवैज्ञानिक संरचना को गहरी चोट पहुंचाई है। नतीजा यह है कि आज बच्चे समय से पहले वयस्क हो रहे हैं-शरीर से नहीं, मानसिकता से।

भारतीय परिवार-व्यवस्था, संस्कार और मूल्य-व्यवस्था इस संकट की चपेट में और तेजी से आए हैं। पहले जहां बच्चे माता-पिता, शिक्षक और संस्कारों से सीखते थे, आज वे 'रील्स' और 'शॉर्ट वीडियोज' एवं अश्लील सामग्री से सीख रहे हैं। जो सामग्री उनके सामने आ रही है, वह न भारतीय चरित्र से मेल खाती है न जीवन-मूल्यों से। निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा तैयार ये सामग्री बच्चों के मन में गलत आदर्श, गलत नायक और गलत आकांक्षाएं भर रही है। सवाल यह है कि क्या बच्चे स्वयं सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, या सोशल मीडिया उन्हें एक सुनियोजित तरीके से अपनी गिरफ्त में ले रहा है? सच्चाई का उत्तर दूसरा है। इन प्लेटफॉर्मों पर अमर्यादित सामग्री की भरमार है-जिसे देखकर किशोरों में अपराधी प्रवृत्तियों की ओर उन्मुखता बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य, संयम, अनुशासन और चरित्र जैसे भारतीय मूल्य हाशिये पर जा रहे हैं। इसके साथ-साथ एक गंभीर स्वास्थ्य-संकट जन्म ले रहा है। घंटों मोबाइल पकड़े बैठने से बच्चे शारीरिक सक्रियता से दूर हो रहे हैं। मोटापा, नींद की कमी, सिरदर्द, रीढ़ संबंधी विकार और यहां तक कि किशोरावस्था में मधुमेह जैसे रोगों के मामले बढ़ रहे हैं।

मानसिक रूप से स्थिति और भी भयावह है। लगातार स्क्रॉल करने की आदत बच्चों की एकाग्रता को चकनाचूर कर रही है। शिक्षा पर इसका सीधा दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है। जो बच्चे घंटों कल्पना-लोक में विचरण करते हैं, वे वास्तविकताओं से जूझते समय टूटने-बिखरने लगते हैं। उनकी सहनशक्ति कम हो रही है, आत्मविश्वास टूट रहा है, और असफलताओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है-जो कई बार आत्महत्या जैसी भयावह प्रवृत्तियों को जन्म देती है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, व्यभिचार से जुड़ी सामग्री, गुमराह करने वाले 'इन्फ्लुएंसर', फर्जी पहचान, ऑनलाइन हिंसा और डिजिटल व्यसन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार बच्चे अपराधों में नहीं, बल्कि अपराधों के शिकार के रूप में फंसते हैं-लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं दिखता। सोशल मीडिया कंपनियों का रवैया लापरवाह रहा है, क्योंकि उनका लक्ष्य बच्चों की सुरक्षा नहीं, बच्चों का उपयोग करके मुनाफा कमाना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऑस्ट्रेलिया जैसे कठोर कदम उठाए जाने चाहिए? उत्तर है-बिल्कुल होना चाहिए। और वह भी तुरंत।

भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किशोरों और युवाओं का है। यदि यह पीढ़ी सोशल मीडिया के अंधाधुंध प्रभाव में ढल गई, तो भविष्य में हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत की वह पहचान, जहां दुनिया भर में भारतीय प्रतिभा, अनुशासन और बुद्धिमत्ता की मिसाल दी जाती थी, वह धूमिल पड़ने लगेगी। यह संकट केवल सरकार का नहीं है-यह समाज, विद्यालयों, अभिभावकों और मीडिया-संस्थानों का संयुक्त संकट है। अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल देना उनकी 'मांग' समझ में आता है, लेकिन उनको दिशा देना उनका कर्तव्य है। विद्यालयों को बच्चों को डिजिटल शिष्टाचार, डिजिटल योग्यता और डिजिटल अनुशासन के बारे में शिक्षित करना चाहिए। सरकार को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ऐसे नियम बनाने चाहिए, जिनमें सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना पड़े। ऑस्ट्रेलिया ने यह कर दिखाया। और दुनिया सहम गई। अब बारी भारत और अन्य देशों की है। क्योंकि बच्चों का बचपन सिर्फ उनका अधिकार नहीं-पूरे समाज का भविष्य है।

यदि यह बचपन सोशल मीडिया के हाथों बर्बाद होता रहा, तो आने वाले दौर में जो विकृतियां जन्म लेंगी, वे केवल सामाजिक नहीं, राष्ट्रीय संकट बन जाएंगी। यह समय निर्णायक है। थोड़ी-सी भी देर-और समाज को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलियाई पहल ने दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि बच्चों को बचाने का समय अब आ गया है। भारत को भी साहसिक कदम उठाकर यह साबित करना होगा कि वह डिजिटल युग के दुष्परिणामों को समझता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और संस्कारित वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बचपन को बचाइए-क्योंकि यही वह आधार है जिस पर समाज, संस्कृति और सभ्यता खड़ी होती है। और यदि यह आधार कमजोर पड़ गया, तो भविष्य की कोई भी इमारत स्थायी नहीं रह सकती।

यह निजी विचार है।

न्यूरोविज्ञान से अपराधविज्ञान तक: यौन अपराधों की वैज्ञानिक पड़ताल

लेखक ग्रो.(डा.)मनमोहन प्रकाश

यौन हिंसा केवल सामाजिक अव्यवस्था या नैतिक पतन का परिणाम नहीं, बल्कि इसमें जटिल वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिकल और सामाजिक-आर्थिक कारण गहरे जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2024) के अनुसार, लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं अपने जीवनकाल में किसी न किसी रूप में यौन हिंसा का शिकार होती हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की रिपोर्ट में हर वर्ष विश्व में करीब 1.2 करोड़ लड़कियाँ यौन शोषण झेलती हैं। भारत में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी, 2023) के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 32-35 हजार बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कई गुना अधिक है क्योंकि ज्यादातर पीड़ित शिकायत दर्ज नहीं करातीं।न्यूरोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि यौन अपराध केवल यौन इच्छा का परिणाम नहीं हैं, बल्कि मस्तिष्क के आवेग-नियंत्रण, सहानुभूति और नैतिक निर्णय से जुड़े हिस्सों की विकृति इसका कारण हो सकती है। प्री-फ्रंटल कॉर्टेक्स की खराब कार्यक्षमता सोच और नियंत्रण को कमजोर करती है, जबकि अमिग्डाला की अत्यधिक सक्रियता आक्रामकता बढ़ाती है। अनेक अपराधियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के असामान्य स्तर पाए गए हैं, जो हिंसक यौन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। बचपन के आघात और पारिवारिक हिंसा मस्तिष्क के पुरस्कार तंत्र को भी विकृत कर, आवेग नियंत्रण को कमजोर करती हैं।डिजिटल युग में अश्लील सामग्री की बढ़ती उपलब्धता अपराध के स्वरूप को बदल रही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (2024) के अध्ययन के अनुसार अत्यधिक अश्लीलता देखने से डोपामीन स्तर असंतुलित हो जाता है, जिससे तीव्र उत्तेजनाओं की तलाश बढ़ती है। भारत में स्मार्टफोन की पहुँच ने किशोरों को इस मानसिक जोखिम में और अधिक संवेदनशील बना दिया है।अपराधविज्ञान के अनुसार यौन अपराध जैविक कारणों के साथ-साथ सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक असमानता और शक्ति प्रदर्शन से भी जुड़े हैं। इन अपराधों का उद्देश्य यौन संतुष्टि से अधिक प्रभुत्व स्थापित करना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है कि 40-55 प्रतिशत यौन अपराधी नशे की हालत में रहते हैं। शराब और नशीली दवाएं मस्तिष्क की निर्णय क्षमता को प्रभावित कर आवेग नियंत्रण कम कर देती हैं। इसके साथ-साथ बढ़ता आर्थिक तनाव और सामाजिक दबाव भी आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं।न्याय व्यवस्था की कमजोरियाँ भी यौन अपराधों को प्रोत्साहित करती हैं। भारत में उक्त अपराधों की दोषसिद्धि दर मात्र 25-30 प्रतिशत है। लंबी सुनवाई, फोरेंसिक जांच की कमी, साक्ष्य खराब होना और सामाजिक दबाव अपराधियों को दंड से बचाता है। ÷निरोध सिद्धांत÷ के अनुसार भयभीत दंड व्यवस्था ही अपराध कम कर सकती है।इस समस्या का समाधान बहुआयामी होना चाहिए। बच्चों और युवाओं को उम्र-उपयुक्त यौन शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और भावनात्मक संयम सिखाना आवश्यक है। अश्लील सामग्री से बचाव के लिए कार्यक्रम और मानसिक परामर्श प्रभावी हो सकते हैं। समाज में महिलाओं के सम्मान और समानता को बढ़ावा देना जरूरी है, और मीडिया में महिलाओं के वस्तुकरण पर नियंत्रण होना चाहिए।न्यायिक सुधारों में त्वरित न्यायालय, अत्याधुनिक फोरेंसिक तकनीक, डीएनए परीक्षण और अपराधियों के लिए व्यवहार चिकित्सा मददगार सिद्ध हो सकते हैं। पीड़ितों के लिए मनो-आघात चिकित्सा और सुरक्षित पुनर्वास भी सर्वप्राथमिकता है।यौन हिंसा को केवल सामाजिक या नैतिक समस्या नहीं, बल्कि न्यूरोविज्ञान, मनोविज्ञान, अपराधविज्ञान और सामाजिक संरचना के समग्र दृष्टिकोण से समझना चाहिए। तभी एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जहाँ किसी को हिंसा या उत्पीड़न से न डरना पड़े।

सामाजिक सुरक्षा की ओर कदम: श्रम संहिताएँ और डिजिटल ढाँचा

जी. मधुमिता दास

सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ गरीबी कम करने, मजबूती बढ़ाने और न्यायसंगत विकास को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रत्येक निवासी को, उसकी आय, रोजगार की स्थिति या जनसांख्यिकीय विशेषता की परवाह किए बिना, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, बेरोजगारी भत्ता या दिव्यांगता सहायता जैसे न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच प्रदान करता है। भारत अब सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में पहले से कहीं अधिक नजदीक है-एक ऐसी प्रणाली जिसे अधिकांश राष्ट्र, यहाँ तक कि सबसे विकसित देश भी, दशकों तक निरंतर निवेश और प्रयास करने के बाद ही स्थापित कर पाए।

श्रम संहिताओं, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के माध्यम से, देश के पास हर कामगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है –चाहे वह गिग ड्राइवर हो, फैक्ट्री कर्मचारी हो या निर्माण कार्य करने वाला प्रवासी मजदूर हो । सामाजिक सुरक्षा संहिता नौ प्रमुख कानूनों को एकल एकीकृत ढांचे में समेकित करती है। इससे प्रशासनिक जटिलता कम करने, लाभों को हस्तांतरित करने की योग्यता बेहतर बनाने, नियोक्ताओं के लिए अनुपालन सरल बनाने और निगरानी व प्रवर्तन मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसकी बदौलत विशेषकर असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्यमों के कामगार – जहाँ भारत के 90त्न कामगार काम करते हैं–नौकरशाही की अड़चनों में उलझे बगैर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

यह संहिता सरकार को भी यह अधिकार देती है कि वह सभी क्षेत्रों में उद्यमों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी का कवरेज बढ़ा सके, ताकि अब तक असुरक्षित रहे कामगारों को लाभ मिल सके और छोटे उद्यमों में स्वैच्छिक पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष / राज्य सामाजिक सुरक्षा कोष की व्यवस्था प्रदान करती है, जहाँ सरकार का वित्तीय योगदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का योगदान, नियोक्ता और कर्मचारियों का योगदान एकत्रित किया जा सकता है, जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सहायता प्रदान कर सकता है।

लेकिन केवल कानून बनाना भर ही पर्याप्त नहीं है। जो बात वास्तव में भारत को उसके वैश्विक समकक्षों से अलग कर सकती है, वह है उसका उभरता डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तंत्र–ई-श्रम डेटाबेस और आधार प्रमाणीकरण से लेकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्लेटफ़ॉर्म तक। ये सभी उपकरण मिलकर भारत को पारंपरिक कल्याण मॉडल से आगे बढ़ने और एक पोर्टेबल, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम कल्याण प्रणाली बनाने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जो दुनिया की किसी भी प्रणाली से अलग है।

आधारः सार्वभौमिकरण की रीढ़

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश सार्वभौमिकता सुनिश्चित करने के लिए हर निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं जो सीधे लाभों से जुड़ी होती है। भारत के पास आधार - के रूप में यह सुविधा पहले से मौजूद है–जो अत्यंत विश्वसनीय और निशुल्क प्रमाणीकरण प्रदान करता है।

आधार सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़े बाधाः अर्थात, विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और नियोक्ताओं में लाभार्थियों की पहचान और प्रमाणीकरण को हल करता है। प्रवासी कामगारों के लिए, आधार-सक्षम पोर्टेबिलिटी वह कर सकती है, जो पिछली पीढ़ी के कल्याणकारी सुधार हासिल नहीं कर पाए : स्थान की परवाह किए बगैर लाभों तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना। यह प्रणाली नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में डिजिटल आईडी आधारित प्रणालियों की तरह है, जहाँ नागरिक अपनी कल्याण पहचान को अलग-अलग क्षेत्रों और सेवाओं में निर्बाध रूप से अपने साथ रख सकते हैं।

एकीकृत डेटाबेस पर आधारित एकीकृत संहिता

जहाँ एक ओर दुनिया भर में संगठित क्षेत्र के कामगार सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत आते हैं, वहीं नियोक्ता-कामगार के बीच स्थिर रोजगार संबंध नहीं होने के कारण असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होता है । कई देश एकीकृत श्रम कानूनों पर भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत कम देशों के पास भारत के ई-श्रम डेटाबेस जैसा विशाल राष्ट्रीय श्रमिक रजिस्टर मौजूद है। सामाजिक सुरक्षा संहिता में एकीकृत पंजीकरण तंत्र का प्रावधान ई-श्रम के साथ पूरी तरह मेल खाता है, जो पहले से ही 310 मिलियन से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जनसांख्यिकीय, कौशल और व्यवसाय संबंधी डेटा को संग्रहित करता है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रत्येक कामगार की विशिष्ट रूप से पहचान की जाती है और उन्हें एक ई-श्रम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान किया जाता है।

भारत की क्षमता–एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से असंगठित कामगारों की विशिष्ट पहचान करना, उन्हें सीधे पंजीकृत करना और ट्रैक करना–सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए तेज़ पंजीकरण, बेहतर पोर्टेबिलिटी और कामगार डेटा के रियल-टाइम अपडेट की सुविधा प्रदान कर सकती है। भविष्य में, यदि ई-श्रम और ईपीएफओ यूएएन को पोर्टेबल बनाया जाता है, तो असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के बीच श्रमिकों की गतिविधियों को ट्रैक करना संभव होगा। इससे श्रम बाजार की गतिशीलता का विश्लेषण किया जा सकेगा और यह सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण डेटा स्रोत साबित होगा।

यूपीआई और डीबीटीः वह महत्वपूर्ण कड़ी जिसे ज्यादातर देश अभी तक अपना नहीं पाए

कल्याण पर ज्यादा ध्यान देने वाले देश बैंकों और पारंपरिक भुगतान प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। हालाँकि भारत ने दुनिया के सबसे तेज़, कम लागत वाले और इंटरऑपरेबल भुगतान नेटवर्क में से एक यूपीआई की पहल की है। डीबीटी के साथ एकीकृत होने के कारण, भारत के पास सामाजिक सुरक्षा भुगतान को तुरंत और सीधे कामगारों के खाते में पूरे देश में कहीं भी भेज सकने की प्रमाणित क्षमता है।

यह एक ऐसी क्षमता है जिसके लिए विकसित अर्थव्यवस्थाएँ भी संघर्ष करती हैं। महामारी के दौरान, अमेरिका तक में लाखों लोगों को प्रोत्साहन चेक के लिए हफ्तों बाट जोहनी पड़ी थी । इसके विपरीत, भारत ने आपातकालीन कोविड-19 भुगतान लाखों लाभार्थियों तक अभूतपूर्व गति से हस्तांतरित किया था।

केंद्रीय और राज्य सरकारों के पास जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य कवरेज, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से जुड़ी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हैं। इन योजनाओं में ई-श्रम पंजीकृत कामगारों को शामिल करके तथा यूपीआई और डीबीटी का उपयोग करके, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा को बड़े पैमाने पर, उपयोगकर्ता-अनुकूल, पारदर्शी और कुशल तरीके से हासिल किया जा सकता है।

भारत दुनिया से आगे निकल सकता है

इतिहास में पहली बार, भारत के पास सभी महत्वपूर्ण साधनः कानूनी ढांचा (श्रम संहिताएँ), एक राष्ट्रीय श्रमिक रजिस्टर (ई-श्रम), एक सार्वभौमिक पहचान प्रणाली (आधार), एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली (यूपीआई) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) मौजूद हैं । यह संयोजन वैश्विक स्तर पर दुर्लभ है। यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो भारत एक ऐसा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा मॉडल बना सकता है जो केवल समावेशी ही नहीं, बल्कि मूल रूप से डिजिटल आधारित और भविष्य के लिए सुरक्षित भी हो– एक ऐसा मॉडल, जिसका अन्य देश एक दिन अध्ययन करें।

सामाजिक सुरक्षा संहिता केवल एक कानून नहीं है; यह 21वीं सदी में किसी राष्ट्र द्वारा अपने कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके को पुनः परिभाषित करने का अवसर है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम संहिताएँ सभी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के इस अनूठे अवसर को पूरा करें।

(लेखिका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार हैं)

डीजीसीए और इंडिगो की मनमानी का नतीजा

अजीत द्विवेदी

भारत में अब किसी भी घटनाक्रम की, चाहे वह एक बड़े संकट के रूप में क्यों न प्रकट हुआ है, तर्कसंगत या तथ्यात्मक व्याख्या नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश राजनीतिक रूप से इतना विभाजित इतिहास में कभी नहीं रहा है। पूरा देश मोदी समर्थन या मोदी विरोध में बंटा हुआ है। तभी हर घटनाक्रम की व्याख्या इसी बाइनरी में होती है। मोदी विरोधी हर घटनाक्रम को एक निर्धारित दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। उनकी सारी व्याख्या एक ऐसे आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट पर आधारित होती है, जो राहुल गांधी या कांग्रेस के इकोसिस्टम द्वारा रची गई है। इंडिगो संकट की व्याख्या भी उसी संरचनावादी सिद्धांत के आधार पर हो रही है।

अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग बता रहे हैं कि 27 नवंबर को अडानी समूह ने फ्लाइट सिमुलेशन टेक्नीक सेंटर यानी एफएसटीसी का अधिग्रहण किया है। यह देश की सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग संस्था है। अडानी समूह ने 820 करोड़ रुपए में इस कंपनी में 72 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे को इंडिगो संकट से जोड़ा जा रहा है। यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि अब देश में जल्दी ही 20 हजार से ज्यादा पायलटों की जरुरत होने वाली है और उसकी आपूर्ति अडानी के मालिकाना वाले एफएसटीसी से होगी।

सवाल है कि क्या 20 हजार पायलट की जरुरत होगी और अडानी ने पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण किया है इसलिए इंडिगो का इतना बड़ा संकट खड़ा कराया गया है ताकि पायलट की कमी पर फोकस बने और अडानी को पचास, सौ करोड़ रुपए की कमाई हो जाए? यह बहुत बेकार का तर्क है। इंडिगो संकट की वैचारिक खांचे से व्याख्या करने वाले इस समूह का दूसरा निष्कर्ष यह है कि इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब ने 36 करोड़ रुपए के और उसके प्रमोटर राहुल भाटिया ने 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जिनमें से ज्यादातर बॉन्ड भाजपा को दिए गए। तो क्या इस रुपए के बदले में भाजपा की केंद्र सरकार ने इंडिगो को इतना बड़ा संकट खड़ा करने की इजाजत दी? यह निष्कर्ष पूरी तरह से गलत नहीं है तब भी अधूरा है। हो सकता है कि चंदे के लिहाज में सख्त कार्रवाई नहीं हुई हो लेकिन संकट इस वजह से खड़ा नहीं हुआ।

असल में इंडिगो का संकट नागरिक विमानन मंत्रालय व नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए और व्यापक रूप से केंद्र सरकार के निकम्मेपन और एकाधिकारवादी निजी कंपनी इंडिगो की मनमानी का नतीजा है। अगर मौजूदा संकट की बात करें तो सरकार का निकम्मापन यह है कि उसने मार्च 2024 में एक नियम बनाया और उसे लागू करने के लिए एक जुलाई 2025 और एक दिसंबर 2025 की डेडलाइन तय की और इतना समय देने के बाद भी इसे ठीक तरीके से लागू नहीं करा पाई। सवाल है कि क्या डीजीसीए को पता नहीं है कि देश के विमानन सेक्टर में करीब 65 फीसदी का हिस्सा रखने वाली और हर दिन 23 सौ उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो के पास पर्याप्त संख्या में पायलट नहीं हैं?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी

पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 90 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और घर पर ही उपचाररत थे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री समेत कई अहम पद संभाले। पाटिल लातूर लोकसभा सीट से सात बार सांसद चुने गए और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा।

12 अक्टूबर 1935 को चाकुर (लातूर) में जन्मे पाटिल ने आयुर्वेद और कानून की पढ़ाई की। उनका राजनीतिक सफर 1967 में लातूर नगर पालिका से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में उन्होंने रक्षा, वाणिज्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण विभागों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

दो चरणों में होगी देश की जनगणना, केंद्रीय कैबिनेट ने दी बजट को मंजूरी

एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

भारतीय जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्ययोजना

भारतीय जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कार्ययोजना है। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में घरों की सूची बनाने (हाउसलिस्टिंग) और आवास (हाउसिंग) जनगणना शामिल होगी, जिसे अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच संचालित किया जाएगा। दूसरे चरण में 'जनसंख्या गणना' फरवरी 2027 में की जाएगी।

हालांकि, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख,

जम्मू-कश्मीर के बर्फ प्रभावित गैर-समकालिक क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में जनगणना सितंबर 2026 में कराई जाएगी।

मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय पोर्टल का उपयोग

लगभग 30 लाख प्रक्षेत्र (फील्ड) कर्मचारी इस राष्ट्रीय महत्व के विशाल कार्य को पूरा करेंगे। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा की गुणवत्ता और सटीकता बढ़ेगी। डेटा का प्रसार भी बेहतर और अधिक उपयोगकर्ता-हितैषी तरीके से किया जाएगा ताकि नीति निर्माण के लिए आवश्यक सभी आंकड़े मात्र एक क्लिक में उपलब्ध हो सकें।

जनगणना 2027 में देश की पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा। प्रक्रिया में हर घर तक पहुंचना और हाउसलिस्टिंग, हाउसिंग तथा जनसंख्या गणना के लिए अलग-अलग प्रश्नावली भरना शामिल है।

उप-जिला, जिला और राज्य स्तर पर भी जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति - गणनाकार-जो आमतौर पर सरकारी शिक्षक होते हैं और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अपनी नियमित ड्यूटी के साथ-साथ जनगणना का फील्ड वर्क भी करेंगे। उप-जिला, जिला और राज्य स्तर पर भी जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति राज्य और जिला प्रशासन करेगा।

2027 जनगणना पहली डिजिटल जनगणना

जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाएगा, जो एंड्रॉयड और द्धह्स दोनों पर उपलब्ध होगा। पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय में निगरानी के लिए 'सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम' (CMMS) विकसित किया गया है। इसके अलावा HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लिकेशन' का उपयोग प्रभारी अधिकारी करेंगे।

जनगणना 2027 के लिए पूरे देश में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सटीक, प्रमाणिक और समय पर जानकारी साझा करने पर जोर होगा।

लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों की तैनाती

लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों-एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी और जिला/प्रधान जनगणना अधिकारी को डेटा संग्रह, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए तैनात किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को उनकी नियमित ड्यूटी के अतिरिक्त किए जाने वाले इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा।

2011 की जनगणना के अनुसार, देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिनमें 62 करोड़ (51.54त्न) पुरुष और 58 करोड़ (48.46त्न) महिलाएं थीं। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई थी।

दिल्ली में होंगे अब 13 जिले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, शासन होगा और अधिक सुचारू

नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल, सुगम और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली के मौजूदा 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन करते हुए 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। यह निर्णय शासन को सरल, पारदर्शी और समन्वित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने का यह निर्णय वर्षों से लंबित था, जिसे किसी भी सरकार ने निपटाने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने मात्र 10 माह में इस लक्ष्य को पूरा कर दिखाया। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के विजन को धरातल पर उतारने का एक सशक्त उदाहरण है।

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी शासन का केंद्र बिंदु होता है और जनता के जीवन में सरकार की सबसे नज़दीकी इकाई है। दिल्ली की तेज़ी से बढ़ती आबादी, निर्माण गतिविधियों, शहरी विस्तार और नागरिक सेवाओं की जटिलताओं को देखते हुए जिला प्रशासन को और अधिक संगठित, प्रभावी और जवाबदेह बनाना समय की जरूरत था।

पारा गिरते ही फिर गैस चेंबर में तब्दील हुआ दिल्ली-एनसीआर, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार; सांस लेना मुश्किल

नोएडा दिल्ली-एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार 12, 13 और 14 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में शैलो से मॉडरेट फॉग की स्थिति बनी रहेगी।12 दिसंबर को तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे ही अगले तीन दिनों तक तापमान के बने रहने की संभावना जताई गई है। लगातार बढ़ती नमी और ठंडी हवाओं के कारण हवा की गति धीमी पड़ गई है, जिससे प्रदूषक जमीन के पास ही ठहर रहे हैं।

राहुल गांधी ने बुलाई कांग्रेस सांसदों की बैठक, बिना कारण बताए गायब रहे शशि थरूर

नईदिल्ली , कांग्रेस पार्टी और केरल के तिरुवनन्तपुरम से सांसद शशि थरूर के बीच में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं, लेकिन थरूर का व्यवहार कई सवालों को जन्म दे रहा है। राष्ट्रपति की विशेष दावत में शामिल होने के बाद अब शुक्रवार को थरूर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बैठक से बिना बताए अनुपस्थित रहे। हालांकि, उन्होंने बैठक में न आने की सूचना दे दी थी, लेकिन कारण किसी को नहीं बताया।

थरूर के कांग्रेस की बैठक से अनुपस्थित रहने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले वे 30 नवंबर को कांग्रेस की रणनीतिक समूह की बैठक से गायब थे। थरूर गुरुवार रात को प्रभा खैतान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोलकाता गए थे, जिसे कारण में वे समय पर दिल्ली नहीं लौट सके। इससे पहले 30 नवंबर को वह केरल में थे और विमान में होने की वजह से बैठक छूट गई थी।

इंडिगो संकट के बीच कार्रवाई शुरू, डीजीसीए ने 4 उड़ान संचालन निरीक्षकों को निलंबित किया

नईदिल्ली , इंडिगो की उड़ान संकट के बीच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। उसने इंडिगो की सुरक्षा और परिचालन अनुपालन की निगरानी कर रहे 4 उड़ान संचालन निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। विमान नियामक ने कार्रवाई प्रारंभिक जांच के आधार पर किया, जिसमें एयरलाइन के हालिया परिचालन संकट से संबंधित निगरानी में कमियां पाई गई हैं। डीजीसीए ने निलंबन का कारण नहीं बताया है। निरीक्षकों के पास परिचालन अनुपालन और सुरक्षा निगरानी का काम था।

'भारत में- तेरे टुकड़े हो, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए...: संघ प्रमुख

एजेंसी

अंडमान में वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और ऋस्स प्रमुख मोहन भागवत इस मौके पर मौजूद थे। बेओदनाबाद में मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे अपने देश में, अपने देश की भक्ति होनी चाहिए, यहां- 'तेरे टुकड़े हो' ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कैसे होता है? पूरा भारत देश को एक मानकर चलता है, संविधान भी हमारा यही कहता है। तो इस भारत में छोटी-छोटी बातों को लेकर टकराव कैसे होता है?

सावरकर के चरित्र में पूर्णता मिलती है- मोहन भागवत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ÷कीर्तन स्मरण जो सारी बातें करनी है, अनुकरण के लिए करनी है। अनुकरण जिसका करना है वह पूर्ण चाहिए, गलत बातों का अनुकरण, गलती करने वाले का अनुकरण करेंगे, तो गलत बातों का भी अनुकरण होगा। सावरकर जी का चरित्र देखते हैं तो उनके चरित्र में पूर्णता मिलती है। वर्णन बहुत हुआ है, सब प्रकार की प्रतिभा सावरकर जी के पास थी। सावरकर जी का वर्णन करना है तो कई विश्लेषण लगते हैं। उनकी कविताओं को देखेंगे तो एक-एक कविता में उनके व्यक्तित्व का पहलू मिलता है। जिस गीत का हम स्मरण कर रहे हैं उस गीत में भक्ति है, प्रेम ,समर्पण, भक्ति के घटक हैं। आदमी जुड़ जाता है, जुड़ कर तन्मय होता है। देश का दुख उसका दुख बन जाता है। अपना व्यक्तिगत शरीर, मन का, बुद्धि का दुख भूल जाता है।

गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, अब पुलिस 1 साल तक नहीं उठा सकती ये कदम

एजेंसी। देश के कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है।? सूत्रों के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि BNSS की धारा 303 के तहत एक साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी नहीं ले सकती है। आइए जानते हैं कि गृह मंत्रालय के इस आदेश के क्या मायने हैं। गृह मंत्रालय के इस आदेश के मायने निकाले तो इस अहम फैसले के बाद बाद गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का नया ठिकाना अगले एक साल तक एशिया की सबसे

अति सुरक्षित तिहाड़ जेल होगी। अब किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी को अगर अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करनी है तो अब से 1 साल तक वो ऐसा तिहाड़ जेल में जाकर ही कर सकती है।

क्यों जारी हुआ आदेश? सूत्रों के हवाले से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर ये आदेश जारी किया है।

केंद्र सरकार ने बदला मनरेगा का नाम, अब होगी 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना'

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार योजना' करने को मंज़ूरी दे दी है. यह भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को काम की गारंटी देकर उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाना है.

सरकार ने योजना में दो अहम बदलाव भी किए हैं. पहला, गारंटीकृत रोजगार दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. दूसरा, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. इन बदलावों से लाखों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

इस योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)' के रूप में हुई थी. बाद में इसे महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कहा जाने लगा. अब सरकार ने योजना का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना'

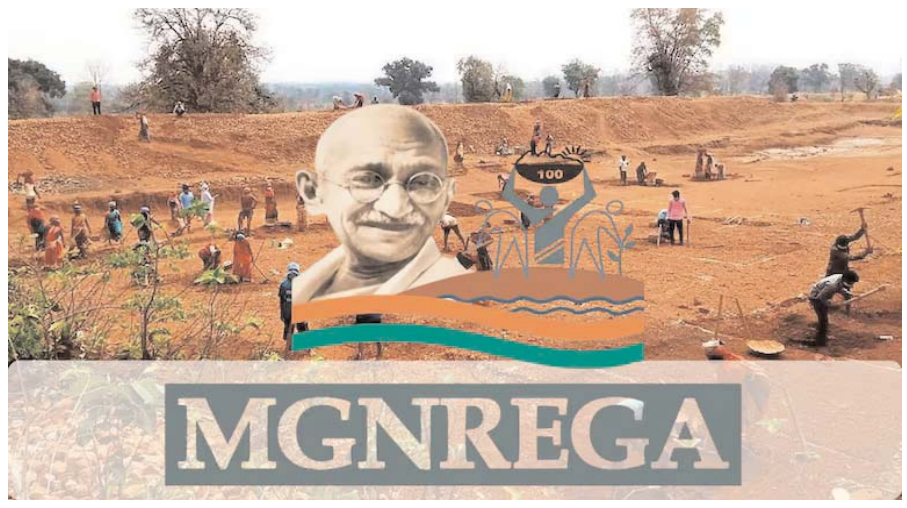

कर दिया है, ताकि ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्यों को एक नई पहचान मिल सके.

यह कानून भारत में 'काम करने के अधिकार' की अवधारणा को मजबूत करता है. इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना है. योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है.

पहले इस योजना में 100 दिनों की मजदूरी की गारंटी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिए जाने से ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा. वहीं, मजदूरी में वृद्धि से मजदूरों की आमदनी में सीधा सुधार होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

यह योजना न केवल रोजगार उपलब्ध कराती है, बल्कि गांवों में जल संरक्षण, सड़क निर्माण, नहर निर्माण, वृक्षारोपण और अन्य विकास कार्यों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करती है.

सरकार के इस फैसले को ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. नए नाम और संशोधनों के साथ यह योजना आने वाले समय में ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने में और अधिक प्रभावी साबित हो सकती है.

चीनी नागरिकों को अब जल्दी मिलेगा भारत का वीजा नियम हुए आसान

एजेंसी।

भारत और चीन के रिश्तों में आई हालिया नरमी ने दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने चीनी प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा प्रक्रिया को तेज करने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें गति पकड़ रही हैं और 2020 के बाद संबंधों में आई खटास को कम करने की दिशा में कुछ ठोस संकेत सामने आने लगे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने वीज़ा प्रक्रिया में मौजूद अतिरिक्त प्रशासनिक जांच की एक महत्वपूर्ण लेयर को हटा दिया है, जिससे वीजा मंजूरी का समय अब चार हफ्तों से भी कम रह गया है। दो सरकारी अधिकारियों ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि नई व्यवस्था

के बाद चीनी प्रोफेशनल्स को बिजनेस वीज़ा मिलने में पहले की तुलना में काफी आसानी होगी। चीन ने भारत के इस कदम को ÷सकारात्मक÷ करार देते हुए इसका स्वागत किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि भारत द्वारा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए उठाया गया यह फैसला संबंधों में सुधार की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन भारत के साथ संवाद और परामर्श जारी रखने को तैयार है ताकि दोनों देशों के रिश्ते वास्तविक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकें। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब 2020 में पूर्वी लद्दाख स्थित LAC पर हुए तनाव ने भारतङ्कचीन संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया था। उस तनाव के बाद न सिर्फ सैन्य गतिविधियाँ प्रभावित हुईं, बल्कि व्यापार, तकनीक और वीज़ा संबंधी प्रक्रियाएँ भी काफी सख्त हो गई थीं।

विदेश : भारतीय औपनिवेशिक काल की कलाकृतियां चोरी हुई

ब्रिटेन के ब्रिस्टल संग्रहालय से 600 मूल्यवान वस्तुएं चोरी

लंदन एजेंसी।

ब्रिटेन के ब्रिस्टल संग्रहालय में चोरी की बड़ी घटना ने लोगों को चौंका दिया है। यहां से ब्रिटिश राज की वस्तुओं सहित 600 से अधिक मूल्यवान वस्तुएं चुरा ली गई हैं, जिसमें भारतीय औपनिवेशिक कलाकृतियां भी शामिल हैं। एवन और समरसेट पुलिस ने बताया कि 25 सितंबर को रात 1 से 2 बजे के बीच 4 लोग ब्रिस्टल स्थित उस गोदाम में घुस गए जहां ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल संग्रह रखा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चोरी संग्रहालय के मुख्य परिसर में नहीं हुई। यह ब्रिस्टल के कंबरलैंड रोड स्थित संग्रहालय के बाहरी भंडारण केंद्र में हुई है। सीसीटीवी फुटेज में 4 श्वेत पुरुषों को संदिग्ध चोर बताया गया है और फुटेज को आम जनता से साझा किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि चोरों के प्रवेश करने का सटीक तरीका स्पष्ट नहीं है, फिर भी वे विभिन्न प्रकार की 600 से अधिक कलाकृतियां चुरा ले गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने चोरी की घटना के 2 महीने बाद जानकारी साझा की है, ताकि नागरिकों की मदद से उन्हें पकड़ा जा

सके। अभी तक चोरी की गई वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है और न ही साझा किया गया है। प्रभारी अधिकारी, डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल डैन बर्गन का कहना है कि अब तक जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज की महत्वपूर्ण समीक्षा, फोरेंसिक जांच और संग्रहालय के अधिकारियों के साथ संपर्क किया गया है।

चोरी गई वस्तुएं अमूल्य थीं, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ब्रिटेन और भारत समेत साम्राज्य के पूर्व सदस्य देशों के बीच संबंधों का दस्तावेज है। वस्तुओं में पदक, बैज, हार, चूड़ियां, अंगूठियां, नक्काशीदार हाथीदांत, चांदी वस्तुएं, कांस प्रतिमाएं, भूवैज्ञानिक नमूने, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी की कमरबंद की बकल, हाथीदांत की बुद्ध प्रतिमा शामिल है। पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल संग्रहालय के 2012 में बंद होने के बाद संग्रहालय नगर परिषद की देखरेख में था। पिछले दिनों 18 अक्टूबर को दिनदहाड़े हेलमेट पहने 4 लोगों ने पेरिस के विश्व प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय से 864 करोड़ रुपये का सामान चुराया था। चोर गैलेरी डीअपोलोन से 7 मिनट में 8 अमूल्य रत्न ले गए, जो 19वीं सदी की रानियों के थे।

कलेक्टर महोबे की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की व्यापक समीक्षा

मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुदृढ़ करने कड़े निर्देश

जिला स्वास्थ्य समिति की शासी एवं कार्यकारी समिति समीक्षा बैठकः हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी और टीकाकरण पर विशेष जोर

जांजगीर-चांपा / संवाददाता।

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति की शासी एवं कार्यकारी समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं, टीकाकरण कार्यक्रम, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, कुपोषण उन्मूलन, स्वास्थ्य संस्थाओं की उपलब्धियों एवं चुनौतियों तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर श्री महोबे ने सभी जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं सतत सुधार विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर फोकस

कलेक्टर ने बैठक में मातृत्व स्वास्थ्य को लेकर विशेष समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गर्भवती महिलाओं का नियमित जांच सुनिश्चित किया जाए। हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी वाले मामलों की लगातार निगरानी की जाए। संस्थागत प्रसव सेवाओं को सुदृढ़ कर मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। कलेक्टर ने कहा प्रत्येक बच्चे को समय पर टीका लगाये जाए। साथ ही टीकाकरण सत्रों की सतत निगरानी, अपूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों की पहचान, ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में चिरायु टीम द्वारा की जा रही स्वास्थ्य स्क्रीनिंग का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान को जिले में व्यापक रूप से लागू किया जाए। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई जाएं। मोबाइल मेडिकल यूनिट की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड व वय वंदना कार्ड की प्रगति की समीक्षा

कलेक्टर ने स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच, ऑनलाइन एंट्री की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड, वय वंदना योजना और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शिविर लगाकर पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड, वय वंदना कार्ड बनाए जाएं। उपचार हेतु आने वाले प्रत्येक मरीज का आभा कार्ड अनिवार्य रूप से तैयार किया जाए। उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्रों में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने, फ इलेरिया एवं डेंगू मरीजों, सघन कुष्ठ खोज अभियान के माध्यम से मरीजों का काउंसिलिंग करने और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने हाइपरटेंशन, मधुमेह जैसी बीमारियों के मरीजों की अधिक से अधिक स्क्रीनिंग कर नियमित निगरानी और उपचार सुनिश्चित करने कहा। इसके साथ ही उन्होंने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, सीएमएचओ श्री यू के मरकाम, सिविल सर्जन श्री एस एस कुजुर, डीपीएम श्री उत्कर्ष तिवारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वच्छ भारत मिशन राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने ग्राम अमरताल, खटोला, कटघरी कल्याणपुर एवं लटिया किया निरीक्षण

जांजगीर-चांपा

11 दिसम्बर 2025/ हमारा शौचालय हमारा भविष्य के अवसर पर राज्य सलाहकार (रा.स्व.भा.मि.ग्रा.) एवं संभाग प्रभारी बिलासपुर श्रीमती मोनिका सिंह द्वारा स्वच्छता गतिविधियों को बेहतर बनाने एवं समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की दिशा में जिले के जनपद पंचायत अकलतरा अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरताल, खटोला, कटघरी कल्याणपुर एवं लटिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राज्य सलाहकार श्रीमती सिंह ने सभी स्वच्छाग्रहियों से गांवों में संचालित कचरा कलेक्शन व्यवस्था, विशेषकर गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण के विषय में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों को घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग श्रेणी में देने हेतु प्रेरित किया तथा स्वच्छ आदतों को अपनाने कहा। राज्य सलाहकार ने यूज़र चार्जेस और प्रोत्साहन राशि से संबंधित जानकारी साझा करते हुए स्वच्छाग्रहियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।उन्होंने गांव में निर्मित सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण कर उनके निरंतर उपयोग, रखरखाव एवं सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सामुदायिक शौचालयों का नियमित उपयोग हो तथा स्वच्छता के मानकों का पूर्ण पालन किया जाए। इस अवसर पर स्वच्छाग्राही समिति के अध्यक्ष, सचिव, महिला समूह की दीदियां, ग्राम सरपंच, सचिव तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मनरेगा कार्यों की रात्रि चौपाल में ग्रामीणों को मिली महत्वपूर्ण जानकारी

डबरी निर्माण, जल संरक्षण और समय पर आवास निर्माण पर दिया गया जोर

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में जिले भर में जन चौपाल एवं रात्रि चौपाल का आयोजन लगातार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित इन चौपालों में ग्रामीणों, प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों, मनरेगा जॉब कार्ड धारकों, स्व सहायता समूह को योजनाओं की प्रगति एवं दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जा रही है।

नवागढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पचेड़ा में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों, निर्माण की समय-सीमा तथा प्रथम किस्त प्राप्त करने वाले हितग्राहियों से सीधा संवाद किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण समय पर पूर्ण करना अनिवार्य है। चौपाल के दौरान पीएम आवास ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री यशवंत सिंह एवं तकनीकी सहायक श्री अब्दुल कामिल सिद्दीकी द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गांवों में जल संरक्षण से संवर्धन अभियान के अंतर्गत डबरी निर्माण कार्य मनरेगा के माध्यम से तेज़ी से संचालित किए जा रहे हैं। ग्रामीणों और किसानों को अधिक से अधिक डबरी बनवाकर बारिश के जल को संरक्षित करने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए प्रेरित किया गया। चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों ने योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे, जिनका समाधान मौके पर ही अधिकारियों द्वारा किया गया।

लाइवलीहुड कॉलेज और जिला अस्पताल में अस्थायी रूप से शुरू होगा मेडिकल कॉलेज

कलेक्टर ने निरीक्षण कर तैयारियों को दिया तेज़ी से पूरा करने का निर्देश

जांजगीर-चांपा / जिले में प्रस्तावित नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के अस्थायी संचालन की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने लाइवलीहुड कॉलेज तथा जिला अस्पताल परिसर स्थित जीएनएम संस्था भवन का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों व मेडिकल टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम जांजगीर श्री सुब्रत प्रधान, डॉ. राकेश नहरेल, प्राध्यापक, शिशु रोग, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर एवं नोडल अधिकारी, नवीन चिकित्सा महाविद्यालय जांजगीर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.के.मरकाम, डीपीएम श्री उत्कर्ष तिवारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.एस.कुजूर सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि स्थायी भवन निर्माण पूर्ण होने तक मेडिकल कॉलेज का संचालन अस्थायी रूप से लाइवलीहुड कॉलेज एवं जिला अस्पताल परिसर में किया जाएगा। लाइवलीहुड कॉलेज में मेडिकल विद्यार्थियों की कक्षाएँ संचालित होंगी। विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था जिला अस्पताल के जीएनएम भवन में होगी। उन्होंने कॉलेज परिसर में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम, कौशल विकास लैब तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण की समुचित तैयार करने के संबंध में निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रयास से छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड में शामिल

प्रदेश में मखाना की खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

मखाना की खेती पर 40 और प्रसंस्करण यूनिट लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान

रायपुर,

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रयासों से प्रदेश में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य में मखाना की खेती कर रहे किसानों को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि हाल ही में धमतरी जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में मखाना की खेती के प्रयासों को देखते हुए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। राज्य में हो रहे मखाने के उत्कृष्ट उत्पादन पर केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रसन्नता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक खेती, जल प्रबंधन, प्रसंस्करण तकनीक और बाजार तक पहुच में सहायता दी जाएगी। इसी तारतम्य में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्रीमती शहला निगार की अध्यक्षता में आज मिशन फार इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट आफ हार्टिकल्चर अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में संचालक उद्यानिकी श्री लोकेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ मखाना प्रारंभ किया गया है। इस योजना में शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में आगामी 4 माह हेतु 180 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना के तहत तालाब में मखाना की खेती करने वाले किसानों को राशि 1.79 लाख रूपए की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत की राशि 72000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है। इसी तरह स्वयं के खेत में मखाना उत्पादन करने वाले कृषकों को राशि 1.32 लाख रूपए की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत की राशि 53000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान है। साथ ही नए तालाब के निर्माण पर राशि 7.00 लाख की इकाई लागत के विरुद्ध 40 प्रतिशत राशि .2.80 लाख का अनुदान देने का प्रावधान है।

मखाना के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु माइक्रो लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 10 लाख रूपए पर 35 प्रतिशत का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह एफपीओ हेतु स्माल लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 39 लाख रूपए पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है तथा निजी क्षेत्र हेतु इकाई लागत राशि 39 लाख रूपए पर 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। लार्ज लेवल मखाना प्रसंस्करण इकाई के स्थापना बाबत इकाई लागत राशि 07 करोड़ रूपए पर 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

मखाना की खेती को बढ़ावा देने हेतु योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ ही एक्पोजर विजिट भी कराया जा रहा है। मखाना खेती को प्रेरित करने हेतु इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय तथा महात्मा गाँधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की उत्कृष्ट खेती का प्रदर्शन भी किया जा रहा है।

जिला समन्वयक एवं संकाय सदस्य के संविदा पद पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

जांजगीर-चांपा / पंचायत संचालनालय अंतर्गत ऋ1ड्डद्बश्चद्दस्र राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत जिले में रिक्त संविदा पदों जिला समन्वयक एवं संकाय सदस्य, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र पर भर्ती हेतु 29 दिसम्बर 2025 तक सायं 05.30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी निर्धारित समय तक आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन 495668 के नाम से पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन केवल डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जिले की वेबसाइट https//janjgir-champa.gov.in तथा जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सूचना पटल से प्राप्त किए जा सकते हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने प्रकाश टण्डन को किया जिला बदर

जांजगीर-चांपा / जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जन्मेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय के प्रस्ताव पर प्रकाश टण्डन को जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए प्रकाश टण्डन पिता गुनाराम टण्डन साकिन बोरसी थाना पामगढ़ को जांजगीर-चांपा जिला एवं सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, बालौदा बाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने तथा 01 वर्ष की कालावधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर (छ.ग.)

Phone No. And Fax No.-0771-2426831 E-Mail- actd.raipur@nic.in

//प्रथम ई–निविदा आमंत्रण सूचना//

छत्तीसगढ लोक निर्माण विभाग अंतर्गत "एकीकृत पंजीकरण प्रणाली" में पंजीकृत तथा सक्षम श्रेणी के ठेकेदारो से फॉर्म "A" (प्रतिशत दर आधार पर) मे निम्नलिखित कार्य के लिए "ई–निविदा" दिनांक 08.01.2026 समय सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:–

क	निर्माणाधीन भवन का नाम एवं स्थान	निविदा की राशि (लाखो में)	अमानत राशि (लाखो में)	कार्य की अवधि
1	गुरूद्वारा मोतीमहल का निर्माण कार्य ग्राम–भंडारपुरी विकासखंड–आरंग जिला–रायपुर	1651.49	5.00 लाख	18 माह (वर्षाकाल सहित)

उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई–प्रोक्यूरमेंट http/eproc.cgstate.gov.in में उक्त निविदा दिनांक 15.12.2025 से देखी जा सकती है।

G-252605439/7

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास रायपुर

खास खबर

श्री राम फायनेंस के दफ्तर में लगी भीषण आग, सामान जलकर खाक

कोरबा कटघोरा रोड स्थित श्रीराम फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बीती रात अचानक भीषण आग भड़क उठी। घटना लगभग रात 12 बजे की है, जब पास के आईसीआईसीआई बैंक एटीएम में तैनात गार्ड ने ऑफिस से उठता धुआँ देखा और तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दी। दमकल दल के मौके पर पहुँचने तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। चार दमकल वाहनों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक ऑफिस का अधिकतर सामान जलकर खाक हो गया।

दिल दहला देने वाला तिहरा हत्याकांड, स्क्रैप व्यवसाय अशरफ मेमन सहित तीन के शव मिले

कोरबा ।

कोरबा शहर में बुधवार देर रात हुए दिल दहला देने वाले तिहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। स्क्रैप व्यवसाय से जुड़े अशरफ मेमन सहित तीन लोगों की उनके फार्महाउस में गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में कबाड़ व्यवसायी अशरफ मेमन, एक स्थानीय युवक तथा बिलासपुर का एक युवक शामिल है। प्रारंभिक जांच में हत्या को बेहद करूर तरीके से अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है। फ्लिहाल पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है इस घटना के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है और दहशत का माहौल है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने इस मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना स्थल कोरबा शहर के समीप स्थित मेमन के फार्महाउस बताया जा रहा है, जहाँ से अहम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच तेज कर दी गई है। इस तिहरे हत्याकांड से पूरे शहर में दहशत का माहौल है।

अभियान : लिंग आधारित हिंसा समाप्ति हेतु 16 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम

कोरबा कलेक्टर श्री अजीत वसंत जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बसंत मिंज एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री गजेंद्र देव सिंह के मार्गदर्शन में नवा बिहान से संरक्षण अधिकारी, महिला सशक्तीकरण केंद्र (हब), जिला मिषन समन्वयक रत्ना नामदेव, जेन्डर विषेषज्ञ तुलेष्वर दुबे,एवं चाईल्ड लाईन के स्टॉफ, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय अधंरीकछार, कस्तुरबा गांधी विद्यालय तथा कन्या छात्रावास एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक पीडब्लूडी विद्यालय, कोरबा में लिंग आधारित हिंसा समाप्ति हेतु 16 दिवसीय (25 नवंम्बर से 10 दिसम्बर) विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

जिसके तारतम्य में योजनांतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना अंतर्गत नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह आदि योजनाओं द्वारा आर्थिक रूप से बालिकाओं को सषक्त बनाया जा रहा हैं। चाइल्ड लाईन 1098, गुड टच बैंड टच, मातृछाया, (नवजात बच्चों को फेंके ना हमें दे) पालना केन्द्र आदि योजनाओं के माध्यम से बच्चो को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

अभियान : लिंग आधारित हिंसा समाप्ति हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम

कोरबा (संवाददाता)।

कलेक्टर अजीत वसंत जिला कार्यक्रम अधिकारी बसंत मिंज एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी गजेंद्र देव सिंह के मार्गदर्शन में नवा बिहान से संरक्षण अधिकारी, महिला सशक्तीकरण केंद्र (हब), जिला मिशन समन्वयक रत्ना नामदेव, जेन्डर विशेषज्ञ तुलेश्वर दुबे,एवं चाईल्ड लाईन के स्टॉफ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय अधंरीकछार, कस्तुरबा गांधी विद्यालय तथा कन्या छात्रावास एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक पीडब्लूडी विद्यालय, कोरबा में लिंग आधारित हिंसा समाप्ति हेतु 16 दिवसीय (25 नवंम्बर से 10 दिसम्बर) विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तारतम्य में योजनांतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना अंतर्गत नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह आदि योजनाओं द्वारा आर्थिक रूप से बालिकाओं को सशक्त बनाया जा रहा हैं। चाइल्ड लाईन 1098, गुड टच बैंड टच, मातृछाया, (नवजात बच्चों को फेंके ना हमें दे) पालना केन्द्र आदि योजनाओं के माध्यम से बच्चो को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में बच्चों को भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता कराकर बालिकाओं को पुरुस्कृत किया गया। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं

जैसे लैंगिक आधारित हिंसा समाप्ति, सखी वन स्टॉप सेंटर, साइबर सुरक्षा, आपातकालीन नम्बरो जैसे डायल 112, 181, 1098, 1930,घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, पॉश एक्ट (शी-बॉक्स) आदि विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई एवं योजनाओं से संबंधित पॉम्पलेट आदि का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में सभी छात्र-छात्राओं और स्कूल के प्रचार्य, शिक्षक -शिक्षिका की उपस्थिति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बाल विवाह मुक्त भारत का शपथ लिया गया।

सिटी ब्यूटीफिकेशन को मूर्तरूप देगा '' क्रिएटिव कार्नर '' , शहर के कोने-कोने में बिखरेगा सौदंर्य

नगर पालिक निगम कोरबा व आर्टिस्ट ग्रुप आफकोरबा की संयुक्त पहल पर '' क्रिएटिव कार्नर '' अभियान का हुआ आगाज

महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने उठाया ब्रश, की पेंटिंग, क्रिएटिव कार्नर की हुई शुरूआत

कोरबा ऊर्जाधानी कोरबा शहर के सौंदर्यीकरण को मूर्तरूप देने निगम द्वारा शुरू कराया गया '' क्रिएटिव कार्नर '' अभियान अब सिटी ब्यूटीफिक्रेशन को मूर्तरूप देगा एवं शहर के कोने-कोने में सौंदर्य बिखरेगा। आर्टिस्ट ग्रुप आफ कोरबा के कलाकार नगर निगम के सहयोग से शहर के मुख्य मार्गो, संपर्क सड़कों, चैक-चैराहों, सार्वजनिक स्थलों एवं उपेक्षित पड़े स्थानों पर ब्रश व रंगों के माध्यम से थीम आधारित पेंटिंग कर अपनी कला का जादू बिखरेगें तथा शहर को नया लुक देंगे। सुभाष चैक से कोसाबाड़ी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग की दीवाल पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने ब्रश उठाकर पेंटिंग की तथा '' क्रिएटिव कार्नर '' की शुरूआत हुई।

नगर पालिक निगम कोरबा व आर्टिस्ट ग्रुप आफ कोरबा की संयुक्त पहल '' क्रिएटिव कार्नर '' अभियान प्रारंभ किया गया है, इसके तहत निगम द्वारा कोरबा के स्थानीय कलाकारों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है, शहर के मुख्य मार्गो, संपर्क सड़कों, चैक-चैराहों सहित ऐसे स्थान जो बरसों से उपेक्षित पड़े हुए थे, इन स्थलों पर थीम आधारित चित्रकारी व पेंटिंग कर स्थलों को सजाया, संवारा जाएगा, जिससे शहर को एक नया लुक मिलेगा, सिटी ब्यूटीफिक्रेशन को दिशा मिलेगी, इससे एक ओर जहॉ शहर का सौंदर्य बढ़ेगा, वहीं पेंटिंग व चित्रों के माध्मय से आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, प्रदूषण से मुक्ति, शहर की स्वच्छता तथा इन सब में उनकी सहभागिता का संदेश व प्रेरणा मिलेगी। इस अभिनव योजना '' क्रिएटिव कार्नर '' की शुरूआत आज सुभाष चैक से कोसाबाड़ी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित दीवाल पर चित्रकारी व पेंटिंग के माध्यम से की गई। आर्टिस्ट ग्रुप आफ कोरबा के सदस्यों की उपस्थिति में महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने ब्रश को थामा तथा वाल पर पेंटिंग कर अभियान की शुरूआत कराई।

सबके सहयोग से कोरबा बनेगा नम्बर वन - इस मौके पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने कहा कि निगम का हमेशा प्रयास रहा है कि हमारा कोरबा शहर स्वच्छ व सुंदर बने, आर्टिस्ट ग्रुप आफकोरबा भी हमारे इस उद्देश्य में आज शामिल हो चुका है, ग्रुप के सदस्य केारबा को सुंदर स्वरूप देने में अपना सहयोग दे रहे हैं। उन्होने कहा कि हमारा कोरबा स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अभी 08 वें नम्बर पर हैं, किन्तु हम कोरबा के नागरिकबंधुओं के सहयोग से अपने शहर को देश में नम्बर 01 पर लाने में सफल होंगे, उन्होने कहा कि मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे निगम आयुक्त अत्यंत ऊर्जावान है तथा शहर को साफ-सुंदर व व्यवस्थित रखने के लिए वे लगातार कार्य कर रहे हैं। क्रिएटिव कार्नर आर्टिस्टों का प्लेटफार्म - इस अवसर पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने कहा कि हमारे कोरबा के आर्टिस्ट अत्यंत क्षमतावान हैं, जरूरत थी कि उनकी क्षमता को सामने लाने हेतु उन्हें प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए, आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्यों से मेरी चर्चा हुई, हमने साथ मिलकर सिटी ब्यूटीफिक्रेशन पर काम करने का निर्णय लिया, परिणाम स्वरूप '' क्रिएटिव कार्नर '' के रूप में कोरबा के स्थानीय कलाकारों को एक प्लेटफार्म मिला, आज इसकी शुरूआत हो चुकी है।

बालको में उत्कृष्ट उत्पादन सम्मान समारोह का आयोजन, 528 कर्मचारी हुए सम्मानित

कोरबा-बालकोनगर। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में शानदार उत्पादन प्रदर्शन और अनुशासन, उत्पादकता और टीमवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उत्कृष्ट उत्पादन सम्मान' समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में कुल 528 बालको कर्मचारियों एवं व्यवसायिक साझेदारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इस उपलब्धि में विभिन्न यूनिट्स की अहम भूमिका रही। कार्बन यूनिट से 151, पॉटलाइन-1 से 115, पॉटलाइन-2 से 171 तथा रोल्ड प्रोडक्ट्स (आरपी) से 91 कर्मचारियों एवं साझेदारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान बालको की विभिन्न इकाइयों ने उत्कृष्ट उत्पादन प्रदर्शन कर संगठन की उपलब्धियों में उल्लेखनीय योगदान दिया। पॉटलाइन-1 के 115 कर्मचारियों को उत्पादन लक्ष्य, प्रचालन अनुशासन और समन्वयपूर्ण कार्यशैली में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नेतृत्व टीम ने उनके सतत प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पॉटलाइन-1 ने प्रदर्शन मानकों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं पॉटलाइन-2 से सर्वाधिक 171 कर्मचारियों को गौरवान्वित किया गया, जो उनकी अनुशासित कार्यप्रणाली, उच्च उत्पादन क्षमता और बेहतर समन्वय का स्पष्ट प्रमाण है। इसके साथ ही कार्बन यूनिट के 151 सदस्यों को उत्पादन, गुणवत्ता और संचालन में निरंतर अनुशासन बनाए रखने के लिए सम्मानित किया गया, जिनके प्रयासों से प्रचालन दक्षता को मजबूती मिली और उत्पादन प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। इसी तरह रोल्ड प्रोडक्ट्स यूनिट से 91 कर्मचारियों को उत्पादन, गुणवत्ता और प्रचालन दक्षता के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मान से नवाजा गया।

कलेक्टर ने दीपका विस्तार परियोजना अंतर्गत अर्जित भूमि में खरीदी बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाने के दिए निर्देश

ड्रोन सर्वे की घोषणा के बाद पाँच गांवों में उबाल, ग्रामीण बोलेरू हमें उजाड़ने की साजिश!

कोरबा । एसईसीएल की कोरबा क्षेत्र अंतर्गत करतली ईस्ट परियोजना को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं.पाली-तानाखार क्षेत्र के विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम की अगुवाई में प्रभावित 5 गांव के ग्रामीणों की बैठक पाली के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई.सभी ने एक स्वर में ड्रोन सर्वे का विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि यदि जोर जबरदस्ती की जाएगी तो ग्रामीण इसका डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं। जानकारी के अनुसार परियोजना हेतु ग्राम पुटा तहसील हरदीबाजार की भूमि का अधिग्रहण हेतु सी.बी.ए (कोल बीयरिंग एक्ट) के तहत धारा 9 (1) का प्रकाशन 23.02.2011 एवं धारा 11 का प्रकाशन 14.09.2011 को किया गया है.इसके सम्बन्ध में एसईसीएल कोरबा के नोडल अधिकारी (भू-राजस्व) के व्दारा पत्र प्रदान किया गया है जिसमें एसईसीएल कोरबा क्षेत्र व्दारा 10.12.2025 से 20.12.2025 के मध्य ड्रोन सर्वे कराये जाने की सूचना प्रदान की गई है।

इस सूचना के बाद ग्राम पंचायत पुटा, उड़ता, नुनेरा, डोंगानाला, करतली के ग्रामीणों ने ड्रोन सर्वे कराये जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध किया है.विधायक सहित ग्रामीणों का कहना है कि एसईसीएल की कोरबा जिले में संचालित अन्य परियोजनाओं के भूविस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय को देख रहे हैं।

हाईकोर्ट ने अरपा सहित अन्य नदियों की उद्गम स्थल के भूमि अधिग्रहण की शासन से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई

बिलासपुर,

राज्य की अरपा सहित तीन अन्य नदियों के संरक्षण के लिए उनके उद्गम स्थल को संवारने जिला कमेटी की घोषणा की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हुई सुनवाई में अरपा नदी के उद्गम स्थल हेतु भूमि अधिग्रहण को लेकर शासन से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई है, मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। इससे पूर्व राज्य से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल आखिर क्यों सूख रहे हैं, यह जानने और इन स्थलों को तलाशने के लिए राज्य सरकार ने कमेटी बनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही यह तय किया कि प्रदेश की दस नदियों के संरक्षण और संवर्धन पर यह कमेटी काम करेगी। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसके आदेश दिए थे। इसके साथ ही सभी नदियों और उनके उद्म स्थल को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का भी आदेश दिया गया। दरअसल रिकार्ड में यह नदियां और उनके उद्गम स्थल फ्लिहाल नाले के रूप में दर्ज हैं। शासन द्वारा सोमवार को पेश जवाब में कहा गया कि सात नदियों अरपा, महानदी, हसदेव, तांदूला, पैरी, केलो, मांड के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कोरबा की लीलागर, पेण्ड्रा की सोनभद्र और तिपान नदी को भी संरक्षित करने निर्देशित किया था। बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में शासन की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश के परिपालन में गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की सोन नदी एवं तिपान नदी के उद्गम स्थलों के लिए ईमानदारी से कोशिशें की जा रहीं हैं।इसी तरह कोरबा जिले में भी लीलागर नदी के संरक्षण के लिए भी उद्गम स्थल को पुनर्जीवित करने एक कमेटी बनाई गई है। इसके बारे में जल संसाधन सचिव ने शपथपत्र पेश किया है। इसमें बताया गया कि, कोरबा जिले में लीलागर और गौरेला-पेंड्रा मरवाही जिले में सोन और तिपान नदियों के उद्गम और रिवाइवल के संबंध में, संबंधित कलेक्टरों को कमेटी या सब-कमेटियां बनाने का निर्देश दिया गया है और नदियों के उद्गम की पहचान और रिवाइवल के लिए सभी ईमानदारी से कोशिशें की जा रही हैं। कोरबा और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के संबंधित कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में रेवेन्यू, पंचायत, फॉरेस्ट, माइनिंग, वॉटर रिसोर्स और म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के अधिकारियों की सब-कमेटी बनाई है। ये सब 20 नवंबर 2025 और 21 नवम्बर 2025 के ऑर्डर के तहत इन नदियों के ओरिजिन की पहचान करने और उन्हें फिर से जिंदा करने का सुझाव देने के लिए हैं। कोर्ट ने शासन से अरपा उद्गम स्थल हेतु भूमि अधिग्रहण की स्टेटस रिपोर्ट मंगाई है।जिसमें इन सभी नदियों के उद्गम स्थल की पहचान कर नदियों के स्त्रोतो का पुनरूद्धार व पुनर्जीवित करने हेतु उपसमिति का गठन किया गया है। इसमेंकलेक्टर,जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अध्यक्ष होंगे जबकि सीईओ जिला पंचायत, वनमंडलाधिकारी, वनमंडल मरवाही, अपर कलेक्टर कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संमाग, मरवाही, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड, जिला खनिज अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पेण्ड्रारोड़, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मरवाही, सीएमओ नगर पालिका परिषद, गौरेला, सीएमओ नगर पालिका परिषद, पेण्ड्रा, सीएमओ नगर पंचायत, मरवाही को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का भूमि पूजन बालोद, दुधली में सम्पन्न

बिलासपुर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर दर्ज करते हुए प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन 8 दिसंबर 2025 को दुधली, जिला बालोद (छत्तीसगढ़) में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गजेन्द्र यादव, शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित रहे। भूमि पूजन विधिवत मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ किया गया।

कार्यक्रम में अमर बी. छेत्री, कार्यकारी निदेशक, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली, इन्द्रजीत सिंह खालसा, राज्य मुख्य आयुक्त तथा राज्य सचिव जितेन्द्र कुमार साहू सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कर्मचारी तथा स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में अतिथियों ने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के युवा विकास, अनुशासन, सेवा व राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बिलासपुर जिले से स्काउटर देवब्रत मिश्रा, संतोष कुमार त्रिपाठी, भूपेन्द्र शर्मा तथा महेन्द्र बाबू टंडन तथा गाइडर श्रीमती बीना यादव, डॉ. भारती दुबे, सुश्री लता यादव, श्रीमती कल्पना सिंह, श्रीमती लक्ष्मी बृजवासी एवं सुश्री निधि कश्यप की विशेष उपस्थिति रही। भूमि पूजन के साथ ही राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी की तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। आयोजन से देशभर के स्काउट-गाइड युवा एक मंच पर जुटेंगे, जिससे राष्ट्र निर्माण की दिशा में नई ऊर्जा व प्रेरणा का संचार होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।

सर्दियों में डाग बाइट की घटना में हुई बढ़ोतरी

सिम्स में 70 तो जिला अस्पताल में 40 लोगों को रोजाना लग रहे इंजेक्शन

बिलासपुर, सर्दियों का मौसम है और गली के कुत्तें लोगों पर कहर बरपा रहे हैं। शहर में इन दिनों अचानक डॉग बाइट के मामले बढ़ गए हैं। वहीं इस दौरान नगर निगम की कार्रवाई बंद होने से कई मोहल्ले और कालोनी से लोगों का रात में निकलना मुश्किल हो चुका है। आवारा कुत्ते इन दिनों आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि रोजाना कुत्तों के आंतक के शिकार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। शहर में सिम्स और जिला अस्पताल में रोजाना 150 से अधिक मरीज रैबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। यह आंकड़ा महज दो अस्पतालों का है, निजी और सरकारी अस्पतालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। ऐसे में डॉग बाइट के शिकार लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बच्चों को बचाना चाहिए सिम्स में रोजाना 70 से 80 लोगों को रैबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें से आधे नए हैं। लोगों को स्ट्रीट डॉग से दूर रहना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों को डॉग से बचाया जाना चाहिए। सिम्स में रोजाना 70 लोगों को रैबिज का इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, इसमें से 30 से 35 लोग नए मरीज रहते हैं, वहीं वहीं जिला अस्पताल में भी 30 से 40 लोग रोजाना इंजेक्शन लगाने पहुंच रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सर्दियों का समय स्ट्रीट डॉग के लिए प्रजनन का समय होता है, ऐसे में कुत्ते आक्रामक व्यवहार करते हैं।

बस्तर संभाग के सातों जिलों और नुवाबाट के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध*

इंदिरा कला संगीत विवि को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग

रायपुर, । भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पाण्डेय ने राजनांदगाँव संसदीय क्षेत्र के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग की है।भाजपा सांसद श्री पाण्डेय ने गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए कहा कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा है। यह विश्वविद्यालय 14 अक्टूबर, 1956 से स्थापित है और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। यह हमारे शास्त्रीय संगीत व नृत्य कला को समर्पित एशिया का पहला विश्वविद्यालय है, जिसमें

कत्थक भरतनाट्यम लोक संगीत सहित अनेक विधाओं की शिक्षा दी जाती है। इस संस्थान में विदेशी छात्र-छात्राएँ भी अध्यनरत हैं, अतः इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा दिया जाए।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदनों की समीक्षा, जिला पंचायत सीईओ ने लंबित प्रकरण जल्द निपटाने के दिए निर्देश

रायपुर, । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार रेडक्रॉस हॉल में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कुमार बिश्वरंजन ने की। बैठक में जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदनों की स्वीकृति की स्थिति तथा लंबित मामलों की संस्था-वार समीक्षा की गई। सीईओ जिला पंचायत ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं समय-सीमा में निराकरण के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि सभी पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिले, यह संस्थाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रवृत्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में जिले की सभी शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संभाग स्तरीय बस्तर ओलम्पिक का किया विधिवत शुभारंभ

आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है....आप आगे बढ़ें, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है - मुख्यमंत्री

बस्तर संभाग के सातों जिलों और नुवाबाट के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध*

बस्तर अब शांति, समरसता और समृद्धि की ओर अग्रसर-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय*

रायपुर /आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है....आप आगे बढ़ें, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर ओलिंपिक 2025 के तहत संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज जगदलपुर के स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में संभाग स्तरीय बस्तर ओलिंपिक का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने समूचे बस्तर संभाग के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बस्तर के गांव-गांव तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास

कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बस्तर अब शांति, समरसता और समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है और प्रदेश तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर के युवाओं ने बड़ी संख्या में इस महती आयोजन में भाग लेकर इसे सफल और ऐतिहासिक बनाया है। सबसे अधिक हर्ष की बात यह है कि बस्तर ओलम्पिक में नुवाबाट के प्रतिभागियों ने भी उत्साहपूर्वक शामिल होकर इसे एक विशेष आयाम प्रदान किया है। बड़ी संख्या में बेटियों और बहनों की सहभागिता यह प्रमाणित करती है कि बस्तर में महिला सशक्तिकरण नई दिशा ले रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार बस्तर के युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें विकास में सहभागी बनाने के लिए कटिबद्ध है। यही कारण है कि बस्तर के युवा लोकतंत्र में आस्था एवं विश्वास के साथ आगे आ रहे हैं और विकास यात्रा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता के विजेता आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। सरकार बस्तर के युवाओं को बेहतर अवसर एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक स्पर्धाओं में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः तीन-तीन करोड़, दो करोड़ तथा एक करोड़ रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलम्पिक न केवल युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने की पहल है, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि बस्तर में खेल अधोसंरचना को और मजबूत किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को उचित मंच मिल सके। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल जितना सिखाता है, उतना ही हार से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बस्तर ओलम्पिक युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सकारात्मक प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर के अंदरूनी इलाकों के युवाओं को अधिक अवसर देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है और भविष्य में यह पहल और अधिक सशक्त रूप में जारी रहेगी। इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप और ओलम्पिक में ब्रॉन्ज मेडल सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ी पद्मश्री एम.सी. मेरीकॉम ने भी उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और शुभकामनाएँ दीं।

संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, सुश्री तनुजा सलाम ने स्वागत उद्बोधन में अवगत कराया कि बस्तर ओलम्पिक की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले के साथ ही नुवा बाट के करीब तीन हजार पाँच सौ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह बस्तर के लिए गौरव का क्षण है और बस्तर के उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है। बस्तर ओलम्पिक में तीन स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गत वर्ष के 1,65,000 प्रतिभागियों की तुलना में इस वर्ष 3,92,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 2,27,000 से अधिक महिला प्रतिभागी शामिल हैं - यह बस्तर में परिवर्तन की नई बयार है।

कार्यक्रम की शुरुआत खिलाड़ियों द्वारा मशाल प्रज्वलन और आतिशबाजी के साथ हुई। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत माता रूकमणी कन्या आश्रम तथा अन्य विद्यालयों की छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गईं। इस अवसर पर विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल, विधायक दंतेवाड़ा श्री चैतराम अटामी, राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण पिस्दा एवं खुशबू नाग, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिलों के नोडल अधिकारी, खेल अधिकारी, प्रशिक्षक एवं बड़ी संख्या में खेलप्रेमी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

पूर्वर्ती के खिलाड़ी विजय डोडी और ओरछा सलोनी बनीं मशालवाहक - बस्तर ओलम्पिक 2025 की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आज अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, मंत्रीगण तथा बॉक्सर पद्मश्री मेरी कॉम द्वारा किया गया। हजारों दर्शकों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलम्पिक की मशाल प्रज्वलित की। इसके बाद यह गौरवशाली मशाल सुकमा जिले के सुदूर अंचल पूर्वर्ती के प्रतिभावान खिलाड़ी विजय डोडी और नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक की निवासी सलोनी कवाची को सौंपा गया। कबड्डी खिलाड़ी विजय डोडी और खो-खो खिलाड़ी सलोनी कवाची ने पूरे उत्साह, ऊर्जा और गौरव के साथ ग्राउंड की परिक्रमा करते हुए मशाल को मुख्य प्रज्वलन स्थल तक पहुंचाया। यह क्षण सुकमा और नारायणपुर जिलों के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और भावनात्मक था - जब माओवाद-प्रभावित एवं दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ हजारों दर्शकों के सामने दौड़ रहे थे।

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रशिक्षण सह कार्यशाला संपन्न

रायपुर, महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों को सुदृढ़ करने हेतु महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर आधारित प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन आज रेडक्रॉस सभाकक्ष, कलेक्टोरेट परिसर, रायपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर तुलसी राठौर ने की। कार्यशाला में स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं विभिन्न शासकीय/अशासकीय विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। सबसे पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग शैल ठाकुर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने सभी विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों को सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया तथा अधिनियम की मुख्य प्रावधानों पर संक्षिप्त चर्चा की। मनोचिकित्सक श्रीमती राशि अग्रवाल ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के मनोवैज्ञानिक प्रभावों जैसे चिंता, अवसाद, आत्मसम्मान में कमी, कार्य प्रदर्शन में गिरावट, सुरक्षा संबंधित भ्रम आदि के बारे में अवगत कराया। उन्होंने पीड़ितों को सहज वातावरण प्रदान करने एवं समिति द्वारा संवेदनशील रवैया अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। परामर्शदाता चंद्रिका कौशल ने बताया कि पीड़ित महिलाएँ 21 दिवस के भीतर अपनी शिकायत आंतरिक या स्थानीय समिति में दर्ज करा सकती हैं।

कोयला क्षेत्रों में 'जस्ट ट्रांज़िशन' पर विस्तृत चर्चा, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लिए ठोस कदमों पर बल

रायपुर – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट (IISD) और स्वनिति इनिशिएटिव के शोधकर्ताओं ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट ÷मैपिंग इंडियाज स्टेट लेवल एनर्जी ट्रांज़िशनः छत्तीसगढ़÷ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शोधकर्ताओं के साथ राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार, ऊर्जा सुरक्षा, और सतत विकास की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की रणनीतियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्षता संबंधी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

शोधकर्ताओं ने मुख्यमंत्री श्री साय को भारत के 52 कोयला उत्पादक जिलों की 'एनर्जी ट्रांज़िशन वल्नरेबिलिटी' पर आधारित एक व्यापक इंडेक्स प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि पारंपरिक कोयला आधारित क्षेत्रों में 'जस्ट ट्रांज़िशन'–अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से न्यायपूर्ण बदलाव–कितना आवश्यक है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह इंडेक्स पुराने कोयला क्षेत्रों में भविष्य की चुनौतियों, रोजगार संरचना, और वैकल्पिक आजीविका के अवसरों का महत्वपूर्ण संकेतक है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह तथा ऊर्जा विभाग के सचिव श्री रोहित यादव उपस्थित थे।

30071 किसानों से 1,57,155.72 मे. टन धान की खरीदी की गई

समितियों से 9,549.00 मे. टन धान का उठाव

दुर्ग (संवाददाता)। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केन्द्रों में अब तक 30071 किसानों से 1,57,155.72 मे. टन धान खरीदी हुई है जिसकी लागत राशि 37,266.41 लाख रूपए है। शासन की पारदर्शी व्यवस्था और तुंहर टोकन के अंतर्गत किसानों को सहुलियतें मिल रही है और वे निर्धारित तिथि अनुसार धान बेचने उपार्जन केन्द्रों में पहुंच रहे हैं। किसानों को धान बिक्री पश्चात् 31,831.66 लाख रूपए का ऑनलाइन भुगतान हो चुका है। उपार्जन केन्द्रों में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए समुचित प्रबंध की गई है। धान खरीदी हेतु केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था है। अब तक 10300 किसानों ने 178.93 हेक्टेयर रकबा समर्पित किया है। खरीफवर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में 6,16,435 मे. टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित है। जिले के समितियों में खरीदे गये धान का उठाव भी शुरू हो गया है। इस हेतु 21,433.60 मे. टन का डीओ/टीओ जारी हो चुका है। जिसमें से 9,549.00 मे. टन धान का उठाव हो चुका है।

जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे विभिन्न स्कूलों में

दुर्ग (जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने आज जिले के दुर्ग विकासखण्ड के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला कुथरेल में पदस्थ समस्त शिक्षक निर्धारित समय पर संस्था में उपस्थित पाये गये। छात्र-छात्राओं को मीनू अनुसार मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने व नियमित अध्यापन कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये।

शासकीय प्राथमिक शाला गांधीभांठा अण्डा में प्रार्थना के समय चन्द्रहास साहू सहायक शिक्षक के द्वारा एक छात्र से दैनिक समाचार का वाचन कराया जा रहा था जिसे अन्य छात्र-छात्राओं द्वारा दोहराया जा रहा था। इस गतिविधियों से बच्चों में दैनिक समाचार पत्र पने की आदत के साथ साथ सामान्य ज्ञान की वृद्धि भी हो रही हैं। श्री साहू द्वारा कराई जा रही इस गतिविधि की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रशंसा की गई। शासकीय प्राथमिक/उ.मा.वि. अण्डा के निरीक्षण दौरान सभी स्टाफउपस्थित पाये गये। 31 दिसम्बर 2025 तक प्राथमिक वर्ग में कक्षा स्तरीय ज्ञान कराये जाने, विद्यालय में स्वच्छता का अभाव पाये जाने पर स्वच्छता बनाये रखने के निर्देश दिये गये है।

सेजेस निकुम का निरीक्षण दौरान निशी चन्द्राकर एवं जुबेर सहायक शिक्षक संविदा, शाला समय तक अपने कार्य पर उपस्थित नही पाये गये। छात्र-छात्रांए नियत समय का पालन नही करते तथा शाला समय पर इर्द गिर्द घुमते पाये गये जिससे संस्था प्रमुख का छात्राओं पर नियंत्रण का अभाव पाये गये हैं। शास. प्राथमिक / माध्यमिक शाला आमटी का निरीक्षण दौरान हेमन्त कुमार टांडिया, पंचराम देवांगन शिक्षक रमेश कुमार देशमुख सहायक शिक्षक विलम्ब से शाला पहुंचे। 31 दिसम्बर 2025 तक कक्षा स्तरीय ज्ञान कराये जाने, विद्यालय में स्वच्छता का अभाव पाये जाने पर स्वच्छता बनाये रखने के निर्देश दिये गये है। शास.उ.मा.वि. रसमड़ा के निरीक्षण दौरान स्वच्छता का अभाव पाया गया जिस पर शाला/शाला परिसर को स्वच्छ रखने के अध्यापन कार्य पर विशेष जोर देने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान नियत समय पर अनुपस्थितों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी 01 जनवरी से बायोमैट्रिक उपस्थिति की जानकारी भी दी। निरीक्षण के दौरान सभी प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक शाला के संस्था प्रमुखों को मध्यान्ह भोजन निर्धारित मीनू अनुसार प्रदाय करने, बारहाखड़ी, पहाड़ा पुस्तक वाचन के नियमित अभ्यास कराने, विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थित सुनिश्चित किये जाने तथा नियत समय पर अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिये। इसी प्रकार हाई/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यो को नियमित प्रायोगिक कार्य करने, ब्लू प्रिंट के अनुरूप 05 वर्षो के प्रश्न पत्रों को हल कराने, तिमाही परीक्षा के आधार पर चिन्हांकित विद्यार्थीयों को सिमित पाठ्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराने एवं प्रायोगिक परीक्षा के बाद भी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तक विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति के निर्देश भी दिये गये।

बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय अब छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट

रायपुर ।बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय अब छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बन गया है। इसकी घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में प्रसन्नता का माहौल है। यह दर्जा उन आर्द्रभूमियों को दिया जाता है जो जैवविविधता, जल संरक्षण और पर्यावरणीय महत्व के लिए वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि कोपरा जलाशय की यह सफलता छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि जलाशय की विशिष्ट पारिस्थितिकी, स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की विविधता तथा जल परितंत्र की समृद्धि ने इसे रामसर मान्यता के योग्य बनाया है।वन मंत्री श्री कश्यप ने राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, पर्यावरणविदों, वन विभाग के अधिकारियों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)